साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 22 • कठुआ, शनिवार 30 मई , 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

एलजी सिन्हा ने चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की प्रगति की समीक्षा की

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू–कश्मीर पुलिस और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नशीले पदार्थों के कारोबार तथा उससे जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे का बढ़ता जाल केवल युवाओं के भविष्य के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह आतंकी गतिविधियों को भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का माध्यम बनता जा रहा है। इसलिए इस समस्या से सख्ती और व्यापक रणनीति के साथ निपटना आवश्यक है।

उपराज्यपाल श्रीनगर स्थित लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जम्मू–कश्मीर में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान की प्रगति की

समीक्षा की गई और नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा इस अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करें।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पुलिस महानिद.`शक को अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती कर नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष कार्यबल को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल करना होगा। इसके लिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सामा. जिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

उपराज्यपाल ने नशा पीड़ित युवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। जिन युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए उचित परामर्श, चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को इन केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि प्रभावित लोगों को समय पर उपचार और

■ शेष पेज 2...

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त करें : अमित शाह

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ श्जीरो टॉलरेंसश नीति सख्ती से लागू करने और पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेटों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेनदेन के कानूनी और वित्तीय

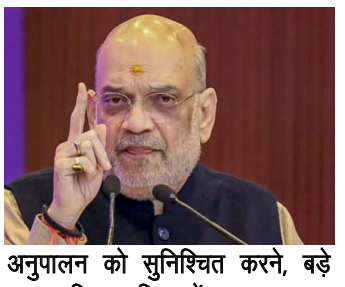

अनुपालन को सुनिश्चित करने, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्तपोषण स्रोतों की जांच करने, फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने

■ शेष पेज 2...

जितेंद्र सिंह का कहना है कि नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को सिविल सेवकों के एक समूह से कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल दक्षता के लिए बल्कि नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए।

यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिक. ारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक शासन अब कठोर पदानुक्रम और एकतरफा संचार के माध्यम से काम नहीं करता है।

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने अधिकारियों को अपने पूरे करियर के दौरान खुले विच.

ारों वाले शिक्षार्थी बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि स्थिर ज्ञान की तुलना में अनुकूलन करने, पुरानी बातों को भूलने और विकसित होने की क्षमता अब अधिक मूल्यवान है।

उन्होंने कहा कि पिछले दशक में प्रशासन की प्रकृति में काफी बदलाव आया है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी पर अधिक जोर

■ शेष पेज 2...

लद्दाख के किसानों को मिली राहत, उपराज्यपाल सक्सेना ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए चेक डैम का शुभारंभ किया

सबका जम्मू कश्मीर

लेह : अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला चट्टानी बांध बनाया गया है। यह बांध उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में बार–बार होने वाली मौसमी जल कमी की समस्या के समाधान के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान का हिस्सा है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को लेह जिले के उपशी में सिंधु नदी पर बने इस बांध का उद्घाटन करते हुए

श्सिंधु जल समृद्धि अभियानश नामक इस पहल की शुरुआत की।

लेह से लगभग 44 किलोमीटर दूर 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्यावरण के अनुकूल पत्थर के बांध को लद्दाख के दूरदराज के गांवों में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक टिकाऊ और कम लागत वाले समाधान के रूप में परिकल्पित किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिंधु नदी के रणनी. तिक रूप से चिन्हित संकरे हिस्सों में पत्थर के बांध बनाकर जल उपलब्धता को बढ़ाना है, जहां नदी के पानी का दोहन आसान और अधिक प्रभावी हो जाता है।

प्रवक्ता ने कहा, ष्स्थानों का चयन स्थानीय ग्रामीणों और समुदायों के परामर्श से किया

■ शेष पेज 2...

एफआरए उल्लंघन मामलों की जांच हेतु दो समितियों का गठन

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के वन मंत्री जावेद राणा ने बुधवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में वन क्षेत्रों में हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और कहा कि वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन की जांच के लिए दो अलग–अलग जांच समितियां गठित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि

पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मंगलवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके में निचली शिवालिक पर्वतमाला के रायका बांदी वन क्षेत्र में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें 30 से अधिक ढांचों को ध्वस्त कर

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

एलजी सिन्हा ने चल...

परामर्श मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों को परित्यक्त इमारतों, नदी तटबंधों और अन्य संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि ऐसे स्थानों का उपयोग अक्सर नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसलिए इन इलाकों में नियमित जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।

उपराज्यपाल ने नशे के कारोबार से जुड़े बड़े तस्करों के नाम सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा, तभी इसके प्रभावी परिणाम सामने आएंगे।

बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों और रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और युवा सहभागिता गतिविधियों के आयोजन का जिम्मा सौंपा। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेल और शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम हैं। यदि युवाओं को बेहतर अवसर और स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे।

उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएं। अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से ही नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि नशे के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेन्द्र कुमार, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह, विद्युत विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी कुमार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्रकर भारती, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, विद्यालय शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से...

और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को बीकानेर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शाह ने भारत–पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का आकलन किया। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ राज्य अधिकारी और पांच सीमावर्ती जिलों – बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और फलोदी – के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान विकसित करने का निर्देश दिया गया है ताकि ये समस्याएं दोबारा न उभरें। शाह ने नागरिकों, राज्य तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवर तैयार करने पर जोर दिया। अधिक. ारियों ने बताया कि गृह मंत्री ने अवैध निर्माणों, विशेष रूप से आंत. रिक सीमाओं के 0 से 15 किलोमीटर के भीतर, के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति को सख्ती से लागू करने और ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने का आह्वान किया। उन्होंने घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवाद वित्तपोषण और अन्य सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य तंत्र को शामिल करते हुए सीमा प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ष्अंतिम मील शासन को मजबूत करने, आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने, बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और सीमावर्ती आबादी का समर्थन करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी)–प्प के सफल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।ष् बैठक में शाह ने सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं की शत प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और साइबर अपराधों से निपटने के लिए श्1930श् कॉल सेंटर के प्रभावी उपयोग का आह्वान किया। बयान में कहा गया, "इन मुद्दों पर दो महीने बाद फिर से समीक्षा और प्रतिक्रिया ली जाएगी; इसलिए, जिलों को परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।"

जितेंद्र सिंह का ...

दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ष्अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकारष् के दर्शन का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल दक्षता के लिए बल्कि नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए।

सिंह ने कहा कि भावी प्रशासकों से तकनीकी दक्षता को सहानुभूति, संवेदनशीलता और नैतिक सार्वजनिक आचरण के साथ संयोजित करने की अपेक्षा की जाएगी।

इस संवाद के दौरान मंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन, शासन संबंधी चुनौतियों, नेतृत्व की जिम्मेदारियों और सिविल सेवकों से जनता की बदलती अपेक्षाओं पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया।

उन्होंने उन्हें तटस्थता बनाए रखने, नागरिकों के लिए सुलभ रहने और दृश्यता के बजाय सार्थक सार्वजनिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सिंह ने इंडिया/2047 को महज एक मील का पत्थर बताने के बजाय एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि इस पीढ़ी के अधिकारी आने वाले दशकों में भारत के उत्थान के प्रमुख चालक बनेंगे।

उन्होंने उनसे विनम्रता, अनुशासन और राष्ट्रीय उद्देश्य की व्यापक भावना के साथ सार्वजनिक सेवा करने का आग्रह किया।

आईएएस के 2024 बैच में महिला अधिकारियों के लगभग 41 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए, जो सेवा के इतिहास में अब तक की सबसे उच्च लैंगिक भागीदारी में से एक है, सिंह ने कहा कि भारत की सिविल सेवाओं का बदलता स्वरूप पूरे देश में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है, जहां अवसरों तक पहुंच पारंपरिक सामाजिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे विस्तारित हो रही है और युवा भारतीय आकांक्षा, प्रौद्योगिकी और जवाबदेही से प्रेरित एक नई शासन संस्कृ ति को आकार दे रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि महिला अधिकारियों का उच्च प्रतिनिधित्व ष्भारत में चल रहे व्यापक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता हैष्।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति यह दर्शाती है कि अवसर और पहुंच किस प्रकार तेजी से लोकतांत्रिक हो रहे हैं।

यह संवाद सहायक सचिव कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसके तहत 2024 बैच के 184 आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नीति निर्माण, समन्वय तंत्र और प्रशासनिक कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए 4 मई से 25 जून, 2026 तक आठ सप्ताह की अवधि के लिए भारत सरकार के 49 मंत्रालयों और विभागों से जोड़ा गया है।

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए सहायक सचिव कार्यक्रम ने युवा आईएएस अधिकारियों को मिलने वाले प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव में मौलिक रूप से बदलाव किया है।

पिछले एक दशक में इस पहल के विकास को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने अधिकारियों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने में मदद की है जो सेवा की शुरुआत से ही अधिक आत्मविश्वासी, नीति–उन्मुख और संस्थागत रूप से जुड़ी हुई है।

सिंह ने सिविल सेवा चयन के बदलते क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में भी बात की, और बताया कि जिन राज्यों का पहले सीमित प्रतिनिधित्व था, वे अब बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवार दे रहे हैं, जबकि कई पारंपरिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों में करियर संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव देखा जा रहा है, जो उभरते क्षेत्रों और वैश्विक अवसरों की ओर बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि ये बदलाव एक अधिक महत्वाकांक्षी और गतिशील भारत के उदय का संकेत देते हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान बैच के 78 अधिकारी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आए हैं, साथ ही चिकित्सा, कानून, प्रबंधन और मानविकी के पेश. ेवर भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आज के शासन में तकनीकी समझ और अंतःविषयक सोच की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब सरकारी कार्यक्रम अधिक डेटा–आधारित, डिजिटल और नवाचार–उन्मुख होते जा रहे हैं।

लद्दाख के किसानों...

जा रहा है। उपराज्यपाल (एलजी) ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को प्रायोगिक आधार पर एक महीने के भीतर ऐसे तीन और पत्थर के बांध बनाने का निर्देश दिया है। प्रवक्ता ने कहा,

यह परियोजना लद्दाख में किसानों द्वारा बुवाई के मौसम में सामना की जाने वाली एक प्रमुख चुनौती का समाधान करने के लिए बनाई गई है, जब सिंधु नदी कई हिस्सों में उथली हो जाती है, जिससे पारंपरिक मोटरों और पंपों के लिए पहाड़ी कृषि क्षेत्रों तक पानी पहुंच. ाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित चेक डैम से एक विशाल जल संग्रहण क्षेत्र बनता है जो कृषि गतिविधियों के चरम समय में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करने में सक्षम है।

उन्होंने आगे कहा, "नदी तल और आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त पत्थरों का उपयोग करके पूरी तरह से निर्मित यह संरचना सीमेंट या कंक्रीट के उपयोग से बचती है, जिससे यह पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजना बन जाती है।"

इस अवसर पर बोलते हुए, सक्सेना ने कहा कि सिंधु जल समृद्धि अभियान लद्दाख के दूरदराज के गांवों में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, जल सुरक्षा बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

हिम सरोवर परियोजना के शुभारंभ के बाद इसे एक और अभिनव पारिस्थितिक पहल बताते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना को लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए दीर्घकालिक जल और कृषि स्थिरता के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। सक्सेना ने कहा कि पारंपरिक सीमेंट–कंक्रीट संरचनाओं के विपरीत, यह चट्टानी बांध नदी के मार्ग में एक अर्ध–स्थायी अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है और एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो नदी में ऑक्सीकरण को बढ़ाता है, जबकि अतिरिक्त पानी को बहने देता है। प्रवक्ता ने बताया कि उपशी स्थित चेक डैम की लंबाई लगभग 200 फीट है, जिसका आधार 30 फीट और ऊपरी डेक 15 फीट चौड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि नदी तल से पांच फीट ऊपर स्थित इस संरचना को गर्मियों के महीनों में बढ़े हुए जल प्रवाह को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सिंधु नदी में वर्तमान जल प्रवाह लगभग 25 क्यूसेक है, जिसके जुलाई और अगस्त के दौरान लगभग आठ गुना बढ़कर 200 क्यूसेक तक पहुंचने की उम्मीद है। "डिजाइन को जल प्रवाह के चरम समय के दौरान उच्च जल दबाव को सहन करने के लिए तैयार किया गया है।" 12 मई से 18 मई के बीच निर्मित यह परियोजना सात दिनों के भीतर पूरी हो गई, जिसके दौरान एलजी ने प्रगति की निगरानी के लिए तीन बार स्थल का दौरा किया। प्रवक्ता ने बताया कि इस बांध के निर्माण के लिए नदी तल में लगभग 180 मीट्रिक टन चट्टानों को आपस में जोड़ा गया, जिनमें से प्रत्येक का वजन 500 किलोग्राम से 10 मीट्रिक टन के बीच था।

इस बांध ने पहले ही नदी के ऊपरी हिस्से में लगभग 1,500 फीट तक फैला एक जल संग्रहण क्षेत्र बना दिया है, जिसमें अनुमानित 4 करोड़ लीटर पानी जमा है। अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारों पर पानी की गहराई चार से पांच फीट के बीच है, जबकि मध्य भाग में यह लगभग 10 फीट तक पहुंच जाती है।

एफआरए उल्लंघन...

कई करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 60 कनाल वन भूमि को पुनः प्राप्त किया गया।

राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर जांच का आदेश दिया गया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की ज्यादती के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राणा ने यहां पत्रकारों से कहा, "पहली बार, आपके द्वारा झेली गई कठिनाइयों के संबंध में एक जांच आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले, ऐसा कोई जांच आयोग कभी गठित नहीं किया गया था।"

मंत्री ने कहा कि आदिवासी मामलों के विभाग के तहत आदिवासी और वनवासियों के अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जबकि वन विभाग के भीतर एक अन्य जांच का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा, "आपके खिलाफ ज्यादती करने वालों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। यदि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे – चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या वरिष्ठ क्यों न हों।" राणा ने कहा कि जांच से यह निर्धारित किया जाएगा कि विध्वंस अभियान चलाने से पहले ष्ए के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। "जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि उल्लंघन कहां हुआ, इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं, और यदि ये लोग वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें अब तक उनके अधिकार क्यों नहीं दिए गए," उन्होंने कहा।

यह दावा करते हुए कि कई वरिष्ठ अधिकारियों, विभागों और लोक भवन ने शुरू में विध्वंस अभियान के बारे में अनभिज्ञता जताई थी, राणा ने कहा कि घटना सामने आने के बाद उन्होंने प्रशासन, वन विभाग और यहां तक ष्कि लोक भवन से भी जानकारी मांगी थी।

"जब मैंने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि उन्हें इस मामले की कोई जानक. ारी नहीं है। जब मैंने लोक भवन को फोन किया, तो वहां से भी मुझे यही जानकारी मिली कि उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है," उन्होंने कहा।

मंत्री ने कहा कि आदिवासी, खानाबदोश और वनवासी वन अधिक. ार अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि ये लोग वन भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन अगर वे आदिवासी, खानाबदोश या वनवासी हैं, तो वन अधिक. ार अधिनियम के तहत दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं हटा सकती।"

अतिक्रमण विरोधी अभियान के समर्थन में उद्धृत अदालती आदेशों का हवाला देते हुए राणा ने कहा कि न्यायिक निर्देशों में भी वनवासियों और आदिवासी समुदायों से जुड़े मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

बढ़ते तापमान के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से हर संभव सावधानी बरतने का आग्रह किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और ऐसे मौसम में सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तथा स्वयं के साथ दूसरों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक माध्यम पर कई संदेश साझा करते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के अनेक राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेज धूप और अत्यधिक तापमान केवल असुविधा ही नहीं पैदा करते, बल्कि कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे जितना संभव हो सके, दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सावधानी अवश्य बरतें।

उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले लोगों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वर्ग भीषण गर्मी के प्रति अधिक संवे. दनशील होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे बच्चे, वृद्धजन, मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारी और खेतों में काम करने वाले लोग तेज गर्मी और लू का जल्दी शिक. ार हो सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गर्मी से होने वाली थकावट के संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चक्कर आना, मतली, सिरदर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान जैसे लक्षण गंभीर स्थिति का संकेत हो

सकते हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति लू में बदल सकती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करे तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं तथा उसे पानी या ओआरएस उपलब्ध कराएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी रखने और दूसरों को भी पानी पिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के इन कठिन दिनों में दया और मानवता का भाव बहुत मायने रखता है। किसी जरूरतमंद को पानी उपलब्ध कराना भी एक बड़ा सेवा कार्य हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि संभव हो तो लोग अपने माता–पिता, दादा–दादी और अन्य प्रियजनों से फोन पर संपर्क कर उनका हालचाल पूछें। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को समय–समय पर पानी पीने, धूप से बचने और आराम करने की सलाह देना जरूरी है, क्योंकि अधिक उम्र में शरीर गर्मी को सहन करने में कठिनाई महसूस करता है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को पानी, ओआरएस तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर की गई छोटी सहायता भी किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है।

मोदी ने केवल मनुष्यों ही नहीं बल्कि पक्षियों और जानवरों का भी ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों और पशुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है। लोगों से अपने घर, छत, बालकनी, दुकान या कार्यालय के बाहर पानी का बर्तन रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि पानी से भरा एक छोटा कटोरा किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवन रेखा बन सकता है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में करुणा और संवेदनशीलता ही समाज को मजबूत बनाती है।

इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उसे लू की स्थिति माना जाता है, जबकि 47 डिग्री से अधिक तापमान को भीषण लू की श्रेणी में रखा जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते तापमान के कारण आने वाले वर्षों में गर्मी की तीव्रता और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन की ओर से भी लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।

दस महीने बीत जाने के बाद भी, पुल के बह जाने से जम्मू के गांवों का संपर्क टूट गया है और स्थानीय लोग नावों पर निर्भर हैं

सबका जम्मू कश्मीर

कतल बटल (नागरोटा) : जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित तवी नदी पर बने एक महत्वपूर्ण पुल के बाढ़ में बह जाने के लगभग दस महीने बाद भी, नागरोटा के कतल बटल क्षेत्र के सैकड़ों निवासी अपनी दैनिक यात्रा के लिए नावों पर निर्भर हैं। आने वाले मानसून के मौसम से लंबे समय तक अलग–थलग रहने का नया डर पैदा हो गया है। यह पुल 4,000 से 5,000 की आबादी वाले कई छोटे गांवों के लिए एकमात्र सड़क संपर्क था और पूजनीय मंदिर तक पहुंचने का एक प्रमुख मार्ग था। पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ में यह पुल बह गया था। तब से, ग्रामीणों, छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को स्कूलों, कार्यस्थलों और बाजारों तक पहुंचने के लिए नावों से नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। निवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान जब भी तवी नदी में बाढ़ आती है, तो सुरक्षा कारणों से नौका सेवाएं बंद होने के कारण उनका जीवन लगभग ठप्प हो जाता है।

"हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दस महीने से अधिक समय से हमारा संपर्क टूटा हुआ है, क्योंकि कई गांवों को जोड़ने वाला हमारा एकमात्र सड़क मार्ग अचानक आई बाढ़ में बह गया था। इस दौरान सरकार ने कुछ नहीं किया," कटाल बटाल के निवासी राजेश कुमार ने कहा।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा बार–बार दिए गए आश्वासन कार्रवाई में तब्दील नहीं हुए हैं, जिससे यह क्षेत्र अलग–थलग पड़ गया है और निवासी दैनिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

"पुल गिरने के बाद पहले कुछ महीनों तक छात्रों, कर्मचारियों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए केवल एक ही नाव उपलब्ध थी। अब तीन नावें हैं, जो प्रतिदिन कई गांवों के सैकड़ों लोगों को सेवा प्रदान करती हैं," संतोष सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि विधायकों ने तवी नदी पर पुल को जोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, "हमें उपेक्षित और अलग–थलग कर दिया गया है। यह इस सरकार के लिए शर्म की बात है।"

आधार नागरिकता प्रमाण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग प्रक्रिया सही ठहराई

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए दस्तावेजीकरण ढांचे को बरकरार रखते हुए कहा कि यह न तो मनमाना है और न ही वैधानिक योजना से बाहर है।

चुनाव आयोग की स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आयोजित करने के आयोग के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

124 पृष्ठों के फैसले में, मुख्य न्यायाधीश ने जनगणना प्रक्रिया के तहत आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ीकरण व्यवस्था की वैधता पर अलग से विचार किया।

फैसले में कहा गया कि चुनाव आयोग को निवास और पात्रता जैसी वैधानिक शर्तों को स्थापित करने में दस्तावेजों के साक्ष्य मूल्य के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का अधिकार है।

फैसले का एक मुख्य बिंदु जनगणना प्रक्रिया में आधार कार्ड की वैधता था।

न्यायालय ने आधार कार्ड पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 12 अंकों के इस विशिष्ट

पहचानकर्ता से संबंधित कानून इसे नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा इसे मतदान के लिए वैधानिक पात्रता स्थापित करने हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में न मानने का निर्णय उचित है। न्यायालय ने आगे कहा,

ष्आधार को बाहर रखने के संबंध में, आयोग द्वारा दिए गए औचित्य की जांच आधार अधि. नियम के आलोक में की जानी चाहिए। आधार कार्ड को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा इसे नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। "ऐसे अभ्यास में जहां आयोग को कानून के अनुसार पात्रता से संतुष्ट होना आवश्यक है३", इसमें कहा गया।

हालांकि, फैसले में लोक प्रतिनिधित्व अधि. नियम (आरपी) की धारा 23(4) का उल्लेख किया गया, जो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के सीमित उद्देश्य के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देता है।

फैसले ने अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की और चुनाव आयोग को बिहार की संशोधित मतदाता सूची में पहचान सत्यापन के लिए आधार को "अतिरिक्त 12वें दस्तावेज" के रूप में मानने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर सरकारने भार्गी-कुनान सड़क दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दो इंजीनियरों को निलंबित किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर सरकार ने डोडा जिले के गंडोह ब्लॉक में भार्गी से कुनान सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हुई दुखद घटना की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। सरकारी आदेश संख्या 184–पीडब्ल्यू (आर एंड बी) दिनांक 26 मई, 2026 के अनुसार, लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग के मुख्य अभियंता (तकनीकी सचिव), इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार को सड़क के इस हिस्से पर 6.00 मीटर लंबे पुलिया के निर्माण से संबंधित घटना की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने जांच अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस बीच, उनके आचरण की जांच लंबित रहने तक, सरकार ने दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिक. ारियों में प्रभारी सहायक कार्यकारी अभियंता इंजीनियर नवीन कुमार और पीएमजीएसवाई डिवीजन थथरी उपमंडल गंडोह के कनिष्ठ अभियंता इंजी. नियर इम्तियाज अहमद शाह शामिल हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान, दोनों अधिक. ारी मुख्य अभियंता। पीएमजीएसवाई जम्मू के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे और नियमों के अनुसार निलंबन भत्ता पाने के पात्र होंगे। यह आदेश लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव), अनिल कुमार सिंह आईएएस द्वारा जारी किया गया था।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में 22 प्रतिशत की कटौती करेगी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : लगातार बढ़ती ईंधन कीमता. और बढ़ते परिचालन खर्च के दबाव के बीच एयर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार वित्तीय संकट और बढ़ते घाटे से जूझ रही एयरलाइन आने वाले महीनों में अपनी घरेलू उड़ानों में लगभग 20 से 22 प्रतिशत तक कमी करेगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी लगभग 27 प्रतिशत कटौती किए जाने की जानकारी सामने आई है। कंपनी का कहना है कि यह कदम परिचालन लागत को नियंत्रित करने और मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एयर इंडिया वर्तमान में प्रति सप्ताह लगभग 4 हजार 400 उड़ानों का संचालन करती है। इनमें करीब 3 हजार 600 घरेलू और लगभग 800 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। लेकिन विमान ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों ने एयरलाइन कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव डाल दिया है। इसके चलते एयर इंडिया को भी अपने परिचालन ढांचे में बदलाव करना पड़ रहा है।

कंपनी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जून से अगस्त 2026 के बीच कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में पहले ही समायोजन की घोषणा की जा चुकी थी। अब इसी अवधि में कुछ घरेलू मार्गों पर भी अस्थायी रूप से परिचालन को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। इसके तहत कुछ मार्गों पर उड़ानों की संख्या कम की जाएगी ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके और बढ़ती लागत के प्रभाव को कम किया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि घरेलू क्षेत्र में उड़ानों की संख्या में 20 से 22 प्रतिशत तक कमी की जा सकती है। इससे उन मार्गों पर यात्रियों को अधिक प्रभाव पड़ सकता है जहां पहले से सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं। हालांकि एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अस्थायी है और परिस्थितियां सामान्य होते ही सेवाओं को फिर से बहाल किया जाएगा।

एयर इंडिया के अनुसार विमान ईंधन की ऊंची कीमतों का असर लगातार एयरलाइन उद्योग पर पड़ रहा है। विमान ईंधन किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का बड़ा हिस्सा होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और करों के कारण ईंधन की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे विमानन कंपनियों के लिए संचालन महंगा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विमानन क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। महामारी के बाद यात्रियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ी है, लेकिन बढ़ती ईंधन कीमतों और अन्य परिचालन खर्चों ने एयरलाइन कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर असर डाला है। कई कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं और अब उन्हें खर्च कम करने के लिए उड़ानों में कटौती जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं।

मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटक शिमला की ओर उमड़ पड़े; 72 घंटों में 70,000 वाहन शहर पहुंचे

सबका जम्मू कश्मीर

शिमला : उत्तर और पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लगातार बढ़ रही आवाजाही के कारण शहर में यातायात दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर लंबे जाम की स्थिति बन रही है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 दिनों के दौरान शिमला पहुंचने वाले वाहनों की संख्या 6 लाख 31 हजार तक पहुंच चुकी है। इनमें से लगभग 70 हजार वाहन केवल पिछले 72 घंटों के भीतर शिमला पहुंचे हैं। अचानक बढ़ी इस भीड़ ने शहर की यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है। हालांकि गर्मी के मौसम का पर्यटन सत्र अभी पूरी तरह अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद शिमला में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और हर वर्ष गर्मियों के मौसम में यहां बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के कारण लोगों ने समय से पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़–कालका मार्ग के माध्यम से सबसे अधिक वाहन शिमला पहुंचे हैं। पिछले 24 दिनों में इस मार्ग से लगभग 3 लाख 70 हजार वाहन राजधानी में दाखिल हुए। इसके अलावा कई वाहन किन्नौर, बिलासपुर और कुल्लू मार्गों से भी पहुंचे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान वाहनों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है, जिससे यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि पर्यटकों की अचानक बढ़ी संख्या के कारण शहर में पहले से मौजूद पार्किंग समस्या और गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल पिछले एक सप्ताह में लगभग 1 लाख 54 हजार 450 वाहन शिमला पहुंचे हैं। इनमें से करीब 70 हजार वाहन बीते 72 घंटों के दौरान आए, जिससे यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। शिमला को पांच अलग–अलग जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन में एक राजपत्रित अधिकारी को यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस बल को भी विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए स्वयंसेवकों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस लगातार पर्यटकों को वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दे रही है ताकि शहर के भीतर भीड़भाड़ कम की जा सके। ऊपरी शिमला की ओर जाने वाले वाहनों को शोघी–मेहली मार्ग की ओर मोड़ा जा रहा है ताकि मुख्य मार्गों पर दबाव कम हो सके।

प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। जून के पहले सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का मौसम सामान्य रूप से अपने चरम पर पहुंचता है। लेकिन इस बार मैदानी क्षेत्रों में असामान्य गर्मी के कारण पर्यटक पहले ही राज्य में पहुंचने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग ठंडे स्थानों की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 31 मई को पंचायत चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को पर्यटन स्थलों पर तैनात किया जाएगा ताकि यातायात और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से सड़क किनारे वाहन न खड़े करें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

शिमला के अलावा मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा और डलहौजी जैसे अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

कविता

टग्गे दी मार

सानु बडा चबात लगा जिसले पता सानु लगा
तुसेंगी मारी गेआ टग्गा तुन्दा पज्जी गेआ
मग्गा।
फराटी मारने करी आउ गेआ घरै बाहर
गप्प कड़ाका करने ताई दिखना कोई थ्हार।
जियां आउं गली बिच गैं ही टकाई,
दूरा मिगी टग्गा नजरी गेआ आई।
डरै कन्ने आउ बिन्दक पराला पैर रक्खां
टग्गा मिगी दिक्खै कडी़–कडी़ अक्खां।
सोचेआ हा आउं चुप चपीता जाना लंगी
पता मिगी लग्गा जिसलै सीगें पर लेआ टंगी,
मसूस मिगी होआ मेरा त्रुटी गेआ मांस
अखीं अग्गे घुम्मन लग्गे धरत ते घास।
पलै बिच लोक सारे किठे गे होई
चान चक्क बुडड़े गी गेआ के्ह होई।
ईक स्याना बोलेआ बिन्द मुस्काइए,
टग्गे ने अज्ज लछकाए दा बनकाइए
कक्ख नी ओन्दा इसी नेई तुस घबराओ
आटो करो सालम इसी अस्पताल पजाओ।
अस्पताल पुजदे मिगी लम्मे लेआ पाई
पंज सात डाक्टरें मिगी टीके दित्ते लाई।
बुरें आलें मिगी होष ही आई, अम्बुलैंस करी मिगी
घर दित्ता पजाई।
अम्बुलैंस दिक्खी मल्लेदार गे घबराई
हत्थ बिन्दग ल्हाईयै आउं दित्ता समझाई
किछ नेई होआ मिगी आउं ठीक आं पाई।
घरैआली पुच्छै तुसैं नेआ केह् कित्ता
बिना वजै टग्गै तुसेंगी कियां मारी दित्ता।
सच्चो सच्च दसो कुतै सनाई ते नेई कविता।
नेई भली लोके मेरा कसूर नेइयो कोई
ऐह् बी भागवाने होनी ओंदी ऐ कोई।
रोजा रोज लोग मेरा हाल पुच्छन औन
आउं आप बीती उनेंगी लग्गी पेआ सनान।
कौड़ी जैह्र दोआईयां खाई आउं गेआ अक्की
लम्मे पेई खट्टा उप्पर आउं गेआ थक्की।
दिने–रातीं औंदी रवै लक्के मेरी पीड़
घरै आहले दिखदे मिगी बटियै चबीड़।
नूआं मिगी आखन तू कित्ता केह पापा
नान–हक पाया साडे ताईं स्यापा
करनी पौनी सानु दिन–राती तेरी सेवा
मीद नेई तेरे कोला थ्होग किछ मेवा
इनी गल्ल सुनी मिगी शर्म बडी आई
चुप्प करी सुनी लेआ केह करदा पाई।
छह म्हीने परैन्त आउं ठीक गेआ होई
टग्गे आहले पासे नेईयो दिख्खेआ परतोई।
शुकरै परमेस्रै दा बची गेइ जान
वाद्दे दी पौनी ही टब्बरै आस्तै कान
जो किछ होना हा ओ गेआ होई
औखा बेला मेरा गेआ कटोई।
मेरे जेई गलती नेई तुस कदें करेओ,
टग्गें कोलों पाई तुस म्हेषां गै डरेओ।

लखारी –जतिन्द्र खजूरिया

और अब कॉकरोच 'जिहाद

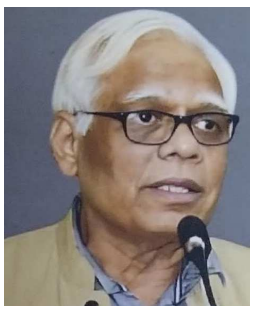

राजेंद्र शर्मा'

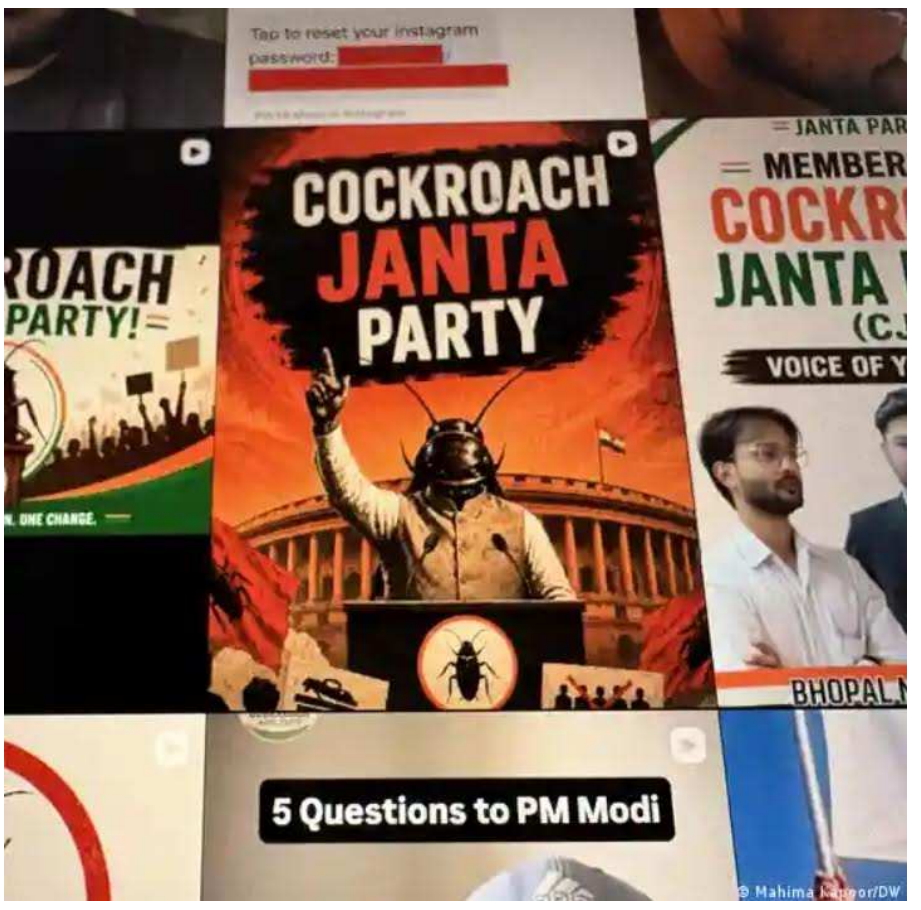

लीजिए, अब कॉकरोच जिहाद शुरू हो गया। जहां से देखो, वहां से निकल–निकल कर कॉकरोच आ रहे हैं। मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच का शोर मचा रहे हैं। और बहाना, न्यायमूर्ति के बोल–बचन से नाराजगी का है, पर असल में एक सौ चालीस करोड़ भारतवासियों के चुने हुए प्रधानमंत्री की हंसी उड़ा रहे हैं।

और हंसी भी उड़ा रहे हैं डिजिटल दुनिया की सुरक्षा के पर्दे के पीछे से, जहां भक्त तो भक्त उनके भगवान भी न पूरी तरह से दबा सकते हैं, न बहुत ज्यादा डरा सकते हैं और न अपने कानफोडू शोर से परेशान कर के भगा सकते हैं।

खुद को कॉकरोच बताते–बताते, जेन ज़ी और दूसरी पीढ़ियों के भी युवा, खुद को कॉकरोच साबित करने पर तुल गए हैं — निडर भी और अजर–अमर भी। यूं ही थोड़े ही कहते हैं कि नाभिकीय प्रलय के बाद भी, पृथ्वी पर कॉकरोच बचे रहेंगे।

क्या कहा? इसमें जिहाद कहां से आ गया? इसे सिर्फ युवाओं की नाराजगी की व्यंग्य भरी हंसी समझने की गलती कोई नहीं करे। बेशक, इसमें युवा हैं। सौ–दो सौ नहीं, हजार–दस हजार नहीं, लाख–दस लाख भी नहीं, करोड़ों युवा हैं। बेशक, इसमें युवाओं की नाराजगी है, बेशुमार नाराजगी। खराब पढ़ाई पर नाराजगी। पेपर लीक पर नाराजगी। फीस की लूट पर नाराजगी। रोजगार नहीं मिलने पर नाराजगी। हर चीज में लुटने पर नाराजगी। झूठे बहानों से बार–बार ठगे जाने पर नाराजगी। कुछ कहने चलें, तो तरह–तरह से मुंह बंद किए जाने पर नाराजगी। और हां हर वक्त, हर जगह, हर तस्वीर में, हरेक स्क्रीन पर, एक ही चेहरा देखने पर भी नाराजगी। और इस नाराजगी का एक व्यंग्य भरी हंसी के रूप में प्रकटीकरण तो हइए। प्रकटीकरण भी विस्फोटक किस्म का। विस्फोट भी इतना तेज कि एक बार को तो भक्तों के भगवान का आसन भी डोल गया। पर यही तो इसके जिहाद होने का सबूत है। यह जो विपक्ष का नेता बार–बार शोर मचा रहा है कि आर्थिक तूफान आ रहा है, सब कुछ तहस–नहस करने वाली आंधी आने वाली है वगैरह, इसका मतलब समझते हैं? इसे सिर्फ आर्थिक तबाही की चेतावनी समझने की गलती कोई न करे। यह तो नाभिकीय प्रलय का इशारा है। यह कॉकरा.`चों को इसका चेत दिलाना है कि प्रलय उनके हक में है। प्रलय में वही बचेंगे। जब प्रलय में वही बचेंगे, तो प्रलय के बाद उन्हीं का राज होगा। यानी यह मोदी जी का आसन गिराने के लिए प्रलय को न्यौतने का षडयंत्र है। कॉकरोचों को इस मोदी विरा.`धी षडयंत्र का मोहरा बनाने का षडयंत्र है। कॉकरा.`चों, क्या तुम्हें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ षडयंत्र का हिस्सा बनना मंजूर है!

और हां! मोदी जी के विरोधियों के इसके दावों से कॉकरोच भ्रमित हर्गिज नहीं हों कि वे तो अजर–अमर हैं। भक्त इस वास्तविक दुनिया में, वास्तविक कॉकरोचों को, वास्तव में मार कर, जगह–जगह अपनी मारकता का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। भक्त दिखा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों और अन्य कमजोरों को ही नहीं, खुद को अजर–अमर मानने वाले कॉकरोचों को मारने में भी, उनके हाथ नहीं कांपेंगे। वर्चुअल दुनिया से उन्हें मिटाने के लिए भक्तों के भगवान की सरक.ारी एजेंसियां ही काफी हैं दृ एक–एक एकाउंट बंद करा देंगी। और रीयल दुनिया में, काला हिट समेत तरह–तरह के कीटनाशकों के साथ, भक्तगण पूरी तरह से तैयार हैं। कोई यह नहीं समझे कि मोदी जी की कमांडरी में भक्तगण, चुनाव जीतना ही जानते हैं। भक्त सड़कों पर युद्ध जीतना और भी जोरदारी से जानते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने पांच दिन में वर्चुअल दुनिया में फोलोअरों की संख्या में, स्वयं भक्तों के भगवान की पार्टी को पीछे छोड़ दिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कॉकरोच रीयल दुनिया में भक्तों के भगवान पर भारी पड़ जाएंगे।

फिर यह तो इसलिए भी जिहाद का मामला है कि यह षडयंत्र लोकल नहीं है, इंटरनेशनल है। मोदी जी के विरोध के चक्कर में, उनके विरोधी उनके खिलाफ षडयंत्र तक में लोकल के लिए वोकल होने को तैयार नहीं हैं। इन्हें षडयंत्र तक इंटरनेशनल चाहिए। और इंटरनेशनल भी अमरीका–इस्राइल वगैरह वाला नहीं, जेहादी। किरण रिजिजू जी ने फौरन गिनती कर के बता दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने, पाकिस्तानी फॉलोवरों के बल पर मोदी जी की पार्टी को वर्चुअल दुनिया में फोलोवरों की संख्या में मात दी है। अब मोदी जी की सरकार में रिजि.जू बार–बार मंत्री बनाए गए हैं, उनकी बात झूठी तो हो नहीं सकती है। अब कॉकरोच पार्टी वाले कहते रहें कि उनके तो पचानवे फीसद फॉलोवर भारतीय हैं, हम नहीं मानेंगे।

वैसे भी कॉकरोच पार्टी के भारतीय फोलोवर तो तब होंगे, जब भारत में कॉकरोच होंगे। पर भारत में तो कॉकरोच हैं ही नहीं। असल में कॉकरोचों को झूठे ही भारतीय बताया जा रहा है, जो भारत में घुसपैठ कराने के षडयंत्र का हिस्सा हो सकता है।

खैर, यह मोदी जी के स्वच्छता मिशन को बदनाम करने के षडयंत्र का हिस्सा तो है ही। सभी जानते हैं कि कॉकरोच गंदी जगहों में पाए होते हैं। अगर यह सच भी हो कि कॉकरोच गंदगी को साफ करते हैं, जिसका दावा खुद को कॉकरोच बताने वालों ने करना शुरू कर दिया है, तब भी कॉकरोचों के होने के लिए पहले तो गंदगी का होना जरूरी है। भारत में भी कॉकरोच तब हुआ करते थे, जब भारत में गंदगी हुआ करती थी। पर 2014 में भारत को गंदगी की मुक्ति के साथ कॉकरोचों से भी मुक्ति मिल गयी। उसके बाद इक्का–दुक्का कोई भारतीय कॉकरोच अभिजीत दिपके की तरह उड़कर कहीं इधर–उधर चला गया हो और बच गया हो, तो बात दूसरी है, पर भारत में अब कोई भारतीय कॉकरोच नहीं हैं। और जब कोई भारतीय कॉकरोच हैं ही नहीं, तो कॉकरोच वोटर कहां से होंगे? तब मोदी जी किसी कॉकरोच जनता पार्टी की परवाह क्यों करें!

वैसे भी मोदी जी कॉकरोचों से डरने वालों में थोड़े ही हैं। छप्पन इंच की छाती सिर्फ दिखाने को ही थोड़े ही ढो रहे हैं। भक्तों और भगवान ने मिलकर, बारह साल में बहुत से जिहाद नाकाम किए हैं, एक जिहाद और सही! कॉकरोचो, तुम अंधेरे कोनों में भागकर छुप जाओ। वर्ना तुम्हारी खैर नहीं। तुमने ट्रंप–नेतन्याहू के फ्रेंड को छेड़ दिया है।

(व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक हैं।)

नरनू शरीफ में 19 जून को होगा बाबा दर्शन शाह जी का विशाल भंडारा, सजेगी सूफी महफिल

पंजाब, हिमाचल, जम्मू–कश्मीर और चंडीगढ़ से पहुंचेगी संगत

राम सिंह

गांव नरनू शरीफ स्थित डेरा बाबा संत बाबा दर्शन शाह जी चिश्ती साबरी में 19 जून को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सूफी महफिल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध उस्ताद कव्वाल बिल्ला एंड पार्टी अपनी मधुर आवाज में सूफियाना कलाम और कव्वालियां पेश करेगी। इसके अलावा कई अन्य कलाकार भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह निशान साहिब एवं चादर चढ़ाने की रस्म के साथ होगी।

इसके उपरांत श्रद्धालुओं के लिए गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा।

गद्दी नसीन सूफी संत बाबा सरदारी शाह जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस धार्मिक आयोजन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और चंडीगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे।

उन्होंने सभी संगतों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा इस पावन आयोजन की खुशियों में शामिल हों।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

गाय–गोबर है चॉकलेटी

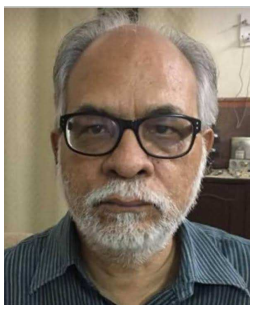

विष्णु नागर

तुमसे न लड़ा जाएगा देश पर आए इस आर्थिक तूफान से। मोदी जी और उनके भाइयो–बहनों, तुम अब रहने दो। तुम्हेंद्द तूफान के समय घर में छिपना और ईश्वर से प्रार्थना करना आता है, लड़ना नहीं। लड़ोगे भी तो काली टोपी पहनकर डंडे से, इसलिए कृपया रहने दो। आजादी की लड़ाई के समय जब यह कृपा तुमने नहीं की थी, तो अब शरीर को क्यों कष्ट देते हो, रहने दो! देश मरता है तो मरने दो। तुम अपनी–अपनी मेलोनियों को मेलोडी चाकलेट खिलाना, मत भूलो!

हां तुम इतना अवश्य कर सकते हो कि इस आर्थिक तूफान से भारत को निकालने के लिए यज्ञ–हवन करो, जैसे कि तुमने ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किया था।अब फिर करो। बार–बार करो। 7, लोक कल्याण मार्ग पर तो अवश्य ही करो। खूब शुद्ध घी और चंदन की लकड़ी की बलि देकर पूरे वातावरण को धुंआ–धुंआ कर दो, शायद इससे आर्थिक तूफान भी धुआं–धुआं हो जाए! इससे भी न रुके, तो तुम 11 हजार लीटर दूध, ढाई सौ साड़ियां और काजू–बादाम नर्मदा में बहा दो। हो सकता है, नर्मदा मैया इससे खुश हो जाएं और इस तूफान से देश को बाहर निकाल लें! मोदी जी से कहो कि कल से वे फिर मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू कर दें। इस बार अपने लिए नहीं, देश की आर्थिक बहबूदी के लिए प्रार्थना करें। शायद इससे रास्ता निकल आए! और हां ताली–थाली बजाने का ट्राइड और टेस्टेड रास्ता तो है ही, उस पर चलें। भारत ने कोरोना संकट का श्सफलतापूर्वक श सामना तो इसी तरह किया था न! क्यों न आज रात नौ बजे से ही ताली–थाली अभियान शुरू कर दिया जाए! और हां, पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम् के सभी छंद गाने का आदेश दिया गया है, उसके सकारात्मक प्रभाव से भी यह संकट दूर हो सकता है। मुसलमानों को बक़रीद चौन से मनाने न देने से भी आर्थिक तूफान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ मुड़ जा सकता है। तुम कुछ और करोगे, मतलब आर्थिक उपाय करोगे, तो देश को और संकट में फंसा दोगे। वह तुम्हारा मार्ग नहीं है। वह तुम्हारा धर्म और कर्म नहीं है।

तूफान सामने है और तुम्हारा लीडर आज भी श्विकसित भारतश के नारे की कीचड़ में लिथड़ा पड़ा है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि विकसित–टिकसित भारत न कुछ था, न कुछ है और न कुछ होने वाला है। अगली दस सदियों का भी उसे समय मिले तो वह श्विकसित भारतश नहीं बना सकता। बिलाशक वह इस देश को नफ़रत में विकासशील से श्विकसित भारतश की मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसकी गरीबी का और श्विकासश कर सकता है। डालर अरबपतियों में देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकता है। सरकारी स्कूल बंद करने की दिशा में उत्तरोत्तर विकास करते–करते वह एक दिन ऐसा ला सकता है, जब पूरे देश में एक भी सरकारी स्कूल न हो, एक भी सरकारी अस्पताल न हो, उनकी जगह आरएसएस की शाखाएं हों या श्प्राचीन मंदिरश हों! वह बचे–खुचे जंगल, जमीन और कारखानों को अडानी को भेंट करने की दिशा में सौ कदम और आगे बढ़ते हुए भारत को और अधिक श्विकसितश बना सकता है!

श्विकसित भारतश यहां अवश्य बनेगा, क्योंकि विदेशी निवेशक यहां से भाग चुके हैं। जो अभी तक नहीं भागे हैं, वे सामान बांध चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए, डालर का रूप धारण करके अमेरिका– चीन आदि मुल्कों में पधार चुके हैं। जिन्होंने इस देश के नागरिक के रूप में अनाप–शनाप धन बटोरा है, वे श्विकसित भारतश का संकल्प पूरा करने के लिए विदेशों की नागरिकता हर साल ग्रहण कर रहे हैं। बेशक इनमें से ज्यादातर भगवा हैं, श्मोदी–मोदीश हैं, मगर उन्हें पता है कि इस भगवा में, इस श्मोदी–मोदीश में उनका और उनकी संततियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जब मोदी जी उनके श्पितृ देशश में आएंगे, तो ये भी श्भारत की मां की जयश बोलने आ जाएंगे।

जरूरत पड़ी तो श्मदर लैंडश के लिए दो आंसू भी बहा देंगे। श्मोदी–मोदी श्का नारा लगा जाएंगे। फिर वहां बस कर ये मोदी का श्विकसित भारतश बनाने की साधना करेंगे। और तो और, जो बड़े–बड़े अरबपति यहां अभी भी डटे और फंसे हुए हैं, वे भी अपना माल धीरे–धीरे विदेशों में खिसका रहे हैं, ताकि मोदी जी का श्विकसित भारतश का स्वप्न साकार हो सके।

तुम्हारे श्विकसित भारतश में इस आर्थिक तूफान से निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फोकस हमेशा से छोटे–छोटे, घटिया–घटिया कामा.ं पर रहता है। इसे–उसे परेशान करने का श्संकल्पश पूरा करने पर रहता है। देश संकट में है और तुम्हारी राज्य सरकारें इस बात पर आमादा हैं कि किसी भी तरह इस देश का मुसलमान बकरीद खुशी से मना न सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, भाजपा सरकार बन चुकी है, फिर भी चौन नहीं है। अभी भी एसआईआर के फंदे में लोगों का गला फंसाने का अभियान जारी है। वंदे मातरम् के छहों छंद मदरसों के छात्रों से गवाने पर फोकस है। संकट कितना ही बड़ा हो, मगर उमर खालिद को छह साल बाद भी लंबी अवधि की जमानत न मिले, इस पर फोकस है। फोकस अडानी को जालसाजी के जंजाल से निकालने पर है।

कई कंपनियों के दिवालिया होने के कगार पर हैं, मगर फोकस राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर है। इनका फोकस विपक्ष को नीचा दिखाने से हटता ही नहीं। दुनिया छूट जाए, मगर गाय और गोबर इनसे छूटना नहीं।

मगर जब इनकी राजनीति की हवा निकालने के लिए पश्चिम बंगाल के मुसलमान गाय को श्राष्ट्रीय पशु श घोषित करने की मांग करते हैं, तो इनकी जीभ तालू से चिपक जाती है! एं–एं भी इनके मुंह से निकलता नहीं!

'(कई पुरस्कारों से सम्मानित विष्णु नागर साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार हैं। जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)'

यह कैसा समाज है, जिसमें अदालतें समझाएं रिश्तों का धर्म

आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्धनता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोगवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं।

ललित गर्ग

किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों, आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, माता–पिता और निर्बल वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन आज का सबसे पीड़ादायक प्रश्न यही है कि जिस भारत ने "मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः" का उद्घोष किया, जिस धरती से "वसुधैव कुटुम्बकम्" का विचार पूरी दुनिया में पहुँचा, उसी भूमि पर आज माता–पिता को अपने ही घर में सम्मान और आश्रय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में देश की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जहाँ वृद्ध माता–पिता को अपने ही बच्चों से संरक्षण, भरण–पोषण, रहने की व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार के लिए न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ा। कहीं बेटे को अदालत यह निर्देश दे रही है कि वह अपनी वृद्ध मां को घर में एक कमरा, अलग स्नानघर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो कहीं दुर्व्यवहार करने वाली संतान को माता–पिता की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह केवल कानूनी घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक पतन की वे चेतावनियाँ हैं जो भविष्य के भारत की तस्वीर पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं।

वास्तव में यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जिस मां ने नौ महीने गर्भ में रखकर संतान को जीवन दिया, जिसने अपना रक्त, ममता और त्याग देकर उसे पाला, उसी मां को अपने ही घर में रहने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़े। जिस पिता ने अपने पसीने और परिश्रम से घर बनाया, बच्चों का भविष्य संवारा, वृद्धावस्था में उसी घर में उसके अधिकार के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, यह स्थिति केवल व्यक्तिगत कृतघ्नता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं के क्षरण का प्रमाण है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, स्मार्ट शहर, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। लेकिन यदि घर के किसी कोने में बैठे वृद्ध माता–पिता अकेलेपन, उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहे हों, तो क्या यह विकास पूर्ण माना जा सकता है? यदि हमारे बुजुर्ग अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर और उपेक्षित हो जाएँ, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ खोखली प्रतीत होती हैं।

आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्धनता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोगवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं। परिणामतः बुजुर्गों का जीवन अकेलेपन, अवसाद और असुरक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। यह सच है कि महानगरीय जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। रोजगार, समयाभाव, आर्थिक दबाव और बदलती जीवनशैली ने नई पीढ़ी की चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद माता–पिता के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति में माता–पिता की सेवा केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन–मूल्य रही है। श्रवण कुमार का आदर्श केवल कथा नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का हिस्सा है।

दुर्भाग्य यह है कि आज संपत्ति और स्वार्थ ने अनेक संबंधों को प्रभावित किया है। अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार दिखाई देते हैं जिनमें संपत्ति के लिए माता–पिता को प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मानसिक यातना दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक वृद्धाश्रम ऐसे माता–पिता से भरे पड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी "गलती" केवल यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी। यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही बढ़ती रही तो भारत भी उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पश्चिमी देशों की तरह माता–पिता और संतान के संबंध केवल कानूनी और औपचारिक होकर रह जाएँ। पश्चिमी समाज में अनेक माता–पिता प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं क्योंकि वे भविष्य में उनसे देखभाल की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन भारतीय समाज का आधार इससे भिन्न रहा है। यहाँ परिवार केवल जैविक इकाई नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था रहा है।

यह भी स्मरणीय है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 जैसे कानून बनाए गए हैं ताकि वृद्ध माता–पिता के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर माता–पिता के संपत्ति अधिक.ारों को सुरक्षित रखा है और दुर्व्यवहार करने वाली संतानों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियाँ भी की हैं। लेकिन कानून केवल सुरक्षा दे सकता है, संवेदना नहीं। अदालतें कमरे दिला सकती हैं, सम्मान नहीं, भरण–पोषण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन ममता और अपनत्व नहीं लौटा सकतीं। यही कारण है कि समाधान केवल कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। परिवारों में संस्कारों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। बच्चों को केवल उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएँ देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्य भी देना होंगे। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को परिवार, सेवा, कृतज्ञता और बुजुर्ग सम्मान जैसे विषयों पर गंभीर पहल करनी चाहिए।

आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में "वृद्ध सम्मान" को भी एक महत्वपूर्ण सूचक बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता–पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकतीं। माता–पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है। यह भी विचारणीय है कि जो संतान आज अपने माता–पिता के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार भविष्य में उसके हिस्से भी आ सकता है। बच्चे केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे अपने माता–पिता को बुजुर्गों की उपेक्षा करते देखेंगे तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

संपादकीय

संतुलन की तलाश

संपादक – राज कुमार

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है। वहीं दूसरी ओर पशुओं के प्रति करुणा और संरक्षण की भावना भी हमारी संस्कृति, परंपरा और कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब पशु अधिकार और मानव सुरक्षा आमने–सामने खड़े दिखाई देने लगें, तब समाज और प्रशासन के सामने संतुलन स्थापित करने की चुनौती उत्पन्न हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या आज एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है। यह केवल पशु कल्याण का विषय नहीं रह गया है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ गया है। देश के अनेक शहरों और कस्बों में लोग, विशेषकर बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग, आवारा कुत्तों के झुंडों के कारण भय और असुरक्षा का अनुभव करते हैं। कई बार कुत्तों के हमलों और काटने की घटनाएँ समाचारों की सुर्खियाँ बनती हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। विडंबना यह है कि अधिकांश नागरिक पशुओं के प्रति क्रूरता का समर्थन नहीं करते। वे यह स्वीकार करते हैं कि पशुओं को भी जीने का अधिकार है और उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती उपस्थिति लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। कई बुजुर्ग नागरिक सुबह–शाम टहलने से डरते हैं। बच्चे पार्कों में खेलने से हिचकते हैं और राहगीर कई बार अपने ही मोहल्ले में असुरक्षित महसूस करते हैं। इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक संवेदनशीलता है। जब नागरिक किसी समस्या को लेकर प्रशासन, नगर निकायों या संबंधित संस्थाओं के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उन्हें समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा होती है। यदि शिकायतों पर महीनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो लोगों का विश्वास व्यवस्था से कमजोर होने लगता है। लोकतंत्र केवल कानून बनाने से नहीं चलता, बल्कि उन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से चलता है। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर समाज दो धड़ों में बंटा दिखाई देता है। एक पक्ष पशु अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरा पक्ष मानव सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। वास्तव में समाधान इन दोनों के बीच टकराव पैदा करने में नहीं, बल्कि संतुलन खोजने में है। पशुओं के प्रति करुणा और नागरिकों की सुरक्षा एक–दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। वैज्ञानिक नसबंदी कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, निर्धारित स्थानों पर भोजन व्यवस्था और प्रभावी जनजागरूकता अभियान इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ आवारा कुत्तों के झुंड लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। वहां तत्काल और व्यावहारिक समाधान लागू किए जाने चाहिए। नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और समय पर कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वह पशुओं के प्रति कितना संवेदनशील है, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को कितना महत्व देता है। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने में भय महसूस करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था का प्रश्न है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भावनाओं के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। पशु संरक्षण और मानव अधिकार दोनों का सम्मान करते हुए ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा कर सकें। तभी एक ऐसा समाज निर्मित होगा जहाँ करुणा और सुरक्षा साथ–साथ चल सकें और नागरिक बिना भय के अपने जीवन का आनंद उठा सकें।

क्या एआई मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी?

ललित गर्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि वह मानव सभ्यता के भविष्य का निर्णायक मोड़ बनती जा रही है। जिस गति से यह तकनीक विकसित हुई है, उसने दुनिया को आश्चर्यचकित भी किया है और चिंतित भी। अभी तक विज्ञान और तकनीक मनुष्य के हाथों में उपकरण थे, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहली ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और सृजन करने की क्षमता के साथ स्वयं को निरंतर विकसित कर रही है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मगुरु, वैज्ञानिक और नीति–निर्माता इसके खतरों को लेकर गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं। हाल ही में वर्तमान पोप लियो चौदहवें द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में व्यक्त की गई चिंताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध को नैतिक नहीं बनाया जा सकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। दुनिया को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पोप ने सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में एआई को मानवता के समक्ष उभरती सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी परिवर्तन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली शक्ति बनती जा रही है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना होना चाहिए। उनका संदेश मानव–केंद्रित विकास की अवधारणा को बल देता है, जिसमें विज्ञान और तकनीक को नैतिकता, मानवीय गरिमा और करुणा के अधीन रखा जाए। पोप की यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मानवीय आह्वान है कि एआई की अंधी दौड़ में मानवता, संवेदना और नैतिकता का क्षरण न होने दिया जाए। आज जब महाशक्तियां एआई के माध्यम से प्रभाव और नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा में लगी हैं, तब पोप का यह संदेश विश्व समुदाय को संयम, उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है।

पोप ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एल्गोरिद्म युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता और तकनीक को मानव विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता। पोप ने चर्च के सामाजिक सरोकारों से जुड़े अपने इस आधिकारिक पत्र में पहली बार एआई को प्रमुख विषय बनाया, जो इस बात का संकेत है कि इसका प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव जीवन, समाज और वैश्विक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से एआई आधारित स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस तकनीक को पूर्णतः मानवीय नियंत्रण में नहीं रखा गया तो यह युद्ध, शोषण और दासता के नए रूपों को जन्म दे सकती है। पोप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को "निरस्त्र" करने का आह्वान करते हुए उसका आशय तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अमानवीय उपयोग पर रोक लगाना बताया। उनका कहना था कि युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय अंततः नैतिकता, करुणा और विवेक पर आधारित होने चाहिए, उन्हें मशीनों के हवाले नहीं किया जा सकता। आज जब अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हैं और युद्ध तकनीकों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, तब पोप का यह संदेश मानवता के लिए एक नैतिक दिशा–सूचक के रूप में सामने आया है कि तकनीक मनुष्य की सेवक बने, स्वामी नहीं; और विकास का केंद्र मानव गरिमा, संवेदना तथा विश्वशांति ही रहे।

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है। आज वही संकट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लाखों लोगों के कार्यों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। ग्राहक सेवा, लेखन, अनुवाद, लेखांकन, सूचना प्रबंधन, प्रोग्रामिंग और कार्यालयी कार्यों में मनुष्य की आवश्यकता तेजी से घट रही है। मशीनें कम लागत, अधिक गति और निरंतर कार्य क्षमता के कारण मनुष्य का स्थान ले रही हैं।

इससे केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक असंतुलन और आर्थिक विषमता भी गहराएगी। जिन देशों और कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण होगा, आर्थिक शक्ति भी उन्हीं के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। इससे विश्व व्यवस्था में असमानता का नया स्वरूप उभरेगा। इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न वैश्विक सुरक्षा का है। आज अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हुई हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व का नया संघर्ष बन चुकी है। जैसे कभी परमाणु हथियारों और घातक अस्त्र–शस्त्रों के माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ था, वैसे ही अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की सामरिक शक्ति बन रही है। स्वायत्त हथियार प्रणाली, बुद्धिमान ड्रोन और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने वाली युद्ध तकनीकें मानवता के लिए भयावह संकेत हैं। यदि युद्ध का निर्णय मशीनों के हाथों में चला गया तो संवेदना, विवेक और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मशीनों के लिए मानव जीवन केवल आंकड़े होंगे। ऐसी स्थिति महाविनाश की संभावना को जन्म दे सकती है। पोप की यह चेतावनी इसी संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है कि युद्ध का अंतिम निर्णय मानव विवेक के अधीन रहना चाहिए।

साइबर सुरक्षा भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण नई चुनौतियों से घिर गई है। बैंकिंग व्यवस्था, विद्युत तंत्र, रक्षा नेटवर्क और संचार प्रणाली आज डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हैं। एआई आधारित साइबर हमले किसी भी राष्ट्र को कुछ घंटों में अस्थिर कर सकते हैं। झूठे संदेश, भ्रामक वीडियो, कृत्रिम चित्र और आवाजों के माध्यम से सामाजिक तनाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। सत्य और असत्य का अंतर मिटने लगा है। यह सूचना तंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए गंभीर संकट है। एआई का एक और चिंताजनक पक्ष है–मानवीय नियंत्रण का कमजोर पड़ना। वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग मानता है कि भविष्य में ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित हो सकती है जो मनुष्य की क्षमता से कई गुना आगे निकल जाए। यदि ऐसा हुआ तो नियंत्रण का प्रश्न सबसे बड़ा संकट बनेगा। यह केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न होगा।

भारत के लिए यह विषय और अधिक महत्वपूर्ण है। भारत युवा शक्ति, विशाल जनसंख्या और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि एआई को बिना स्पष्ट नीति और नियंत्रण के बढ़ने दिया गया तो रोजगार, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भारत को विकास और नियंत्रण दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। एआई को रोकना समाधान नहीं है, लेकिन इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन रखना अनिवार्य है। भारत को ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक विकास के लिए हो, लेकिन रोजगार संरक्षण, डेटा सुरक्षा, नैतिक मानदंड और युद्ध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी एआई के उपयोग हेतु साझा नियम और अंतरराष्ट्रीय संधियां आवश्यक हैं।

आज सबसे बड़ा प्रश्न तकनीक का नहीं, मानवता का है। क्या मनुष्य अपनी बनाई हुई शक्ति पर नियंत्रण बनाए रख सकेगा? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन को समृद्ध बनाएगी या उसे नियंत्रित करेगी? क्या विकास संवेदनाओं से बड़ा हो जाएगा? क्या एआई रूपी विस्फोट मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी? यही वे प्रश्न हैं जिन पर दुनिया को गंभीर चिंतन करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा यदि मानवता केंद्रित रही तो यह सभ्यता को नई ऊंचाइयां दे सकती है, लेकिन यदि यह शक्ति नियंत्रण और नैतिकता से मुक्त हो गई तो यह मानव इतिहास के सबसे बड़े संकट एवं महाविनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज आवश्यकता तकनीकी प्रगति की नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण प्रगति की है–जहां मशीनें विकसित हों, किंतु मानवता सर्वोच्च बनी रहे।

– ललित गर्ग

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

तपती धरती, झुलसता जीवन : जनता के समक्ष हीटवेव की चुनौती

हीटवेव का सबसे बड़ा कारण केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि वह विकास मॉडल है जिसने धरती की प्राकृतिक ढाल को कमजोर कर दिया। जंगल सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण को शीतल रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं।

ललित गर्ग

वर्ष 2026 की गर्मी केवल एक मौसमीय घटना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अप्रैल–मई के दौरान भारत सहित दक्षिण एशिया के अनेक हिस्सों में पड़ी रिकॉर्ड हीटवेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का संकट नहीं, वर्तमान की भयावह वास्तविकता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई शहरों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें सूनी दिखने लगीं, श्रमिकों का श्रम ठहरने लगा और बच्चों, बुजुर्गों तथा गरीब तबकों के सामने जीवन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। यह संकट अचानक नहीं आया। यह दशकों से प्रकृति के साथ किए गए असंतुलित व्यवहार, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई, संसाधनों के दोहन और सुविधावादी जीवनशैली का परिणाम है। प्रकृति ने बार–बार संकेत दिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उन संकेतों को अनसुना किया। आज वही उपेक्षित चेतावनियां लू बनकर हमारे सामने खड़ी हैं।

हीटवेव का सबसे बड़ा कारण केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि वह विकास मॉडल है जिसने धरती की प्राकृतिक ढाल को कमजोर कर दिया। जंगल सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण को शीतल रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन विडंबना है कि विकास के नाम पर जंगलों का तेजी से विनाश हुआ। हर वर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ा, नमी कम हुई, वर्षा चक्र प्रभावित हुआ और गर्म हवाओं की अवधि लंबी होती गई। आज शहर "कंक्रीट के जंगल" बन चुके हैं। महानगरों में हरित क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट, डामर और शीशे की ऊंची इमारतें ले रही हैं। इससे "अर्बन हीट आइलैंड" प्रभाव तेजी से बढ़ा है। शहर अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो चुके हैं। कंक्रीट दिनभर सूर्य की ऊष्मा को सोखता है और रात में धीरे–धीरे छोड़ता है। परिणामस्वरूप रातें भी गर्म होती जा रही हैं और शरीर को राहत नहीं मिल पाती।

दिल्ली, मुंबई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में रात का तापमान पहले की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। गरीब बस्तियों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां न हरित क्षेत्र हैं, न पर्याप्त जल आपूर्ति, न शीतलन के साधन। टीन की छतों वाले घर दिन में भट्ठी बन जाते हैं। गर्मी की मार सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। अमीर वर्ग एयर कंडीशनर और बंद कमरों में राहत खोज लेता है, लेकिन मजदूर, रिक्शाचालक, रेहड़ी वाले और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक खुले आसमान के नीचे झुलसते रहते हैं। विडंबना यह भी है कि गर्मी से राहत का सबसे लोकप्रिय साधन एयर कंडीशनर स्वयं संकट को बढ़ाने वाला कारक बनता जा रहा है। एक एयर कंडीशनर कमरे को ठंडा करता है, लेकिन बाहर उतनी ही गर्म हवा छोड़ता है। इसके साथ ही बिजली की खपत बढ़ती है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला आधारित ऊर्जा से आता है। रेफ्रिजरेंट गैसें अतिरिक्त ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र निर्मित हो गया है–गर्मी बढ़ती है, एसी बढ़ते हैं, उत्सर्जन बढ़ता है और फिर गर्मी और बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर डाल रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि बढ़ती गर्मी और अनिश्चित मौसम के कारण गेहूं, धान और अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। गर्म हवाएं पौधों की वृद्धि रोकती हैं, जल स्रोतों को सुखाती हैं और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में खाद्य संकट भी गहरा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इसका गंभीर प्रभाव दिख रहा है। लू लगना, निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को है। गर्मी का यह संकट सामाजिक और मानवीय संकट भी बन सकता है। जल स्रोतों के सूखने, कृषि संकट और जीवन परिस्थितियों के बिगड़ने से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ सकता है। जैव विविधता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अनेक जीव–जंतु और वनस्पतियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं। हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी करना पर्याप्त नहीं है। हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख विषय के रूप में स्वीकार करते हुए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। सबसे पहले शहरों में हीट एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। प्रत्येक शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण, छायादार मार्ग, सार्वजनिक प्याऊ और शीतलन केंद्रों की व्यवस्था आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों के समय निर्धारण में क्षेत्रीय तापमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीखी दोपहर में श्रमिकों के लिए कार्यावधि सीमित की जाए और उनके लिए विश्राम तथा पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य हो। सरकार को भवन निर्माण नीति में भी परिवर्तन लाना होगा। पारंपरिक भारतीय वास्तुकला–हवादार घर, आंगन, मिट्टी आधारित निर्माण, हरित छतें और प्राकृतिक वेंटिलेशन को बढ़ावा देना चाहिए। कांच की चमचमाती इमारतों और ऊष्मा अवशोषित करने वाले निर्माणों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। "कूल रूफ" तकनीक, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा आधारित शीतलन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वन संरक्षण और वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं, राष्ट्रीय प्राथमिकता बनना चाहिए। शहरों में माइक्रो फॉरेस्ट, पार्क और हरित गलियारों का निर्माण किया जाए। जल निकायों और पारंपरिक तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए क्योंकि वे स्थानीय तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल सरकारें यह लड़ाई नहीं जीत सकतीं। आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। हमें उपभोगवादी जीवनशैली पर पुनर्विचार करना होगा। पानी का संयमित उपयोग, ऊर्जा की बचत, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण अब व्यक्तिगत विकल्प नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हैं।

भारतीय समाज में कभी सार्वजनिक प्याऊ, छायादार विश्राम स्थल और जल सेवा की समृद्ध परंपरा थी। गर्मियों में राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था पुण्य कार्य माना जाता था। आज उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। समाज, धार्मिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन मिलकर जल सेवा और राहत कार्यों का अभियान चला सकते हैं। गर्मी और जल संकट को राजनीति का विषय बनाने के बजाय सहयोग और समाधान का विषय बनाना होगा। जल विवादों और संसाधनों पर स्वार्थपूर्ण राजनीति भविष्य को और कठिन बनाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन को राष्ट्रीय सहमति का विषय बनाया जाए। वर्ष 2026 की यह झुलसाती गर्मी हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने अभी भी प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित नहीं किया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और विकराल होगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जैव विविधता नष्ट होगी, खाद्य संकट गहराएगा और मानव जीवन अधिक कठिन हो जाएगा। यह समय प्रकृति से संघर्ष का नहीं, उसके साथ सामंजस्य का है। हमें विकास की ऐसी दिशा चुननी होगी जिसमें पर्यावरण, मानव जीवन और भविष्य सुरक्षित रह सके। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सूरज की तपिश केवल असुविधा नहीं, अस्तित्व का संकट बन जाएगी।

– ललित गर्ग
लेखक,पत्रकार एवं स्तंभकार
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजन रक्तदान शिविर में 160 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान

सबका जम्मू कश्मीर

नौशहरा/जम्मू। संत निरंकारी मिशन द्वारा चौकी हडन ब्रांच में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,इस मौके पर लगभग 160 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया।रक्तदान शिविर का उद्घाटन एडीसी नौशहरा डॉक्टर प्रीतम लाल थापा,संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज बीपी सिंह, और संत निरंकारी मिशन के अन्य सदस्यों ने किया।

इस मौके पर एडीसी नौशहरा डॉक्टर प्रीतम लाल थापा,ने संत निरंकारी मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि संत निरंकारी मिशन मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है।और सबसे बड़ी बात रक्तदान करने पहुंचे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला खुशी–खुशी से लोग रक्तदान करने के लिय आगे आए।एक यूनिट रक्तदान दो से तीन लोगों की जिंदगी बच सकती है जिस में सब से उत्तम कार्य संत निरंकारी मिशन कर रहा है।इस मौके पर बोलते हुए संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज बीपी सिंह,ने कहा संत निरंकारी मिशन पिछले 40 वर्ष से लगातार पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविरों का आयोजन करता आ रहा है। अब तक मिशन द्वारा 9174 रक्तदान शि. विरों के माध्मम से 15,00,230 यूनिट रक्त संकलित किया जा चुका है जो मानव सेवा के प्रति निरंकारी मिशन की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह शिविर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी की पवित्र याद में लगाए जाते हैं जिन्होंने 24 अप्रैल 1980 को मानवता के भले के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।इसी लड़ी में इस वर्ष भी 24 अप्रैल 2026 को तकरीबन 200 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिससे लगभग 40000 यूनिट रक्त संकलित किया गया और निष्काम भाव से सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मानवता की सेवा में समर्पित किया गया।

समाज सेवा के इसी भाव को आगे बढ़ते हुए रविवार 31 मई 2026 को संत निरंकारी सत्संग भवन चौकी हडन में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया जिस में सरकारी अस्पताल राजौरी तथा मैडीकल कालेज, जम्मू के अनुभवी चिकित्सकों एवं उनकी टीम ने रखतदाताओं की समुचिक जांच के उपरान्त सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से रक्तदान की प्रक्रिया सम्पन्न करवाते हुए 160 यूनिट मानवता की सेवा में समर्पित किये गए।

सम्पूर्ण आयोजन के दौरान स्वच्छता, सतकर्ता एवं सेवा भाव का विशेष ध्यान रखा गया।रक्तदान शिविर नौशहरा,नारिया,मावा,लाम, झांगड, चौकी,ब्रांच के सभी सदस्यों के सहयोग से लगाया गया।संत निरंकारी मिशन की यह पहल जीवनदायनी सेवा तक सीमित न रहकर मानवता, करूणा और उत्तरदायित्व के उच्चतम आदर्श का प्रतीक बनकर उभरी। जहां युगप्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी सत्य,सरलता और सदभावना का मार्ग दिखाते हुए युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाने और उर्जा को समाज सेवा में लगाने की प्रेरणा देते रहे, वहीं बाबा हरदेव सिंह जी ने ष्खत नाड़ियों में बड़े, नालियों में नहीं का संदेश देकर सेवा को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया। और आज वर्तमान सत्गुरू माता सुदीक्षा जी महाराज इसी सेवा भाव को आगे बढ़ा रही हैं।इस अवसर पर निरंकारी भवतों द्वारा ष्मानव को मानव हो प्यारा, इक दूजे का बने सहारा के भाव को जीवंत करते हुए समाज को नशामुक्त बनाने तथा आगे बढ़कर अपनी उर्जा को मानवहित में प्रयोग करने का संदेश दिया।कार्यकम के अंत में चौकी ब्रांच के मुखी गोविन्द लाल,ने कार्यकम में शामिल डॉक्टरों की टीम, रक्तदान दान करने वाले लोगों,जोनल इंचार्ज,सभी ब्रांचों के मुखी संगत और अन्य सभी लोगों का धन्यवाद किया।

आईटीबीपी–लद्दाख समझौता ज्ञापन से किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार खोजने में मदद मिलेगी : एलजी

सबका जम्मू कश्मीर

लेह/जम्मू : लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को कहा कि स्थानीय किसानों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए सुनिश्चित बाजार संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से आईटीबीपी लेह फ्रंटियर और केंद्र शासित प्रदेश के सहक. ारिता विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार खो. जने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। उपराज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ष्लद्दाख में स्थानीय किसाना. ं, सहकारी समितियों और एफपीओ, जिनमें सीमावर्ती गांवों के किसान भी शामिल हैं, के लिए सुनिश्चित बाजार संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से आज आईटीबीपी लेह फ्रंटियर और लद्दाख सहकारिता विभाग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।ष् इस समझौता ज्ञापन के तहत, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ लद्दाख की सहकारी समितियों, एफपीओ और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खरीदे जाएंगे और आईटीबीपी को आपूर्ति किए जाएंगे। सक्सेना ने कहा कि यह पहल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय उपज खरीदने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह पहल सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, ग्रामीण आजी. विका को मजबूत करेगी और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देगी, साथ ही दुर्गम परिस्थितियों में तैनात आईटीबीपी जवानों के लिए ताजा और पौष्टिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।" लद्दाख में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, उपराज्यपाल ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों, धार्मिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और इस समस्या को रो. कने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया जा सके। सक्सेना ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के गिरोहों पर कार्रवाई शुरू करने, स्थानीय टैक्सियों सहित वाहनों की अचानक तलाशी लेने, जोजी ला और सरचू जैसे लद्दाख के प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने और स्कूलों, कॉलेजों और पर्यटन स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने परिवारों और मरीजों के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन के रूप में "112" स्थापित करने का भी आदेश दिया, जिसमें समन्वित देखभाल के माध्यम से परिवहन और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित टीम होगी।

मंत्रिमंडल ने 25,530 करोड़ रूपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ सार्थक–पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'सार्थक–पीडीएस' योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वपूर्ण योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया।

योजना के तहत राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन, भंडारण व्यवस्था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 25 हजार 530 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'पीडीएस में स्वचालन के साथ राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता योजना' को एक व्यापक और आधुनिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक लागू रहेगी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न की आपूर्ति को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाना है।

सरकार का मानना है कि देश में करोड़ों लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं और खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना में तकनीकी सुधारों और डिजिटल प्रणाली के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के माध्यम से राशन की ढुलाई, भंडारण और वितरण में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों के अनुसार योजना के तहत खाद्यान्न परिवहन प्रणाली को अधिक सुचारु बनाया जाएगा। कई राज्यों को दूसरे राज्यों से खाद्यान्न प्राप्त करना पड़ता है, जिसके कारण परिवहन लागत और प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता से राज्य एजेंसियों को इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे समय पर राशन पहुंचाने में सुविधा होगी और वितरण व्यवस्था में देरी की समस्या कम होगी।

योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वचालन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, राशन दुकानों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग तथा लाभार्थियों के आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन शामिल है। सरकार का कहना है कि तकनीकी व्यवस्था मजबूत होने से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और वास्तविक पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

सरकार पहले ही 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' जैसी व्यवस्था लागू कर चुकी है, जिससे लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब 'सार्थक–पीडीएस' योजना के विस्तार से इस व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीकों के प्रयोग से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में किसी प्रकार की कटौती या गड़बड़ी की संभावना कम होगी।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

15 लाख की लागत से बने दो विकास कार्य जनता को समर्पित

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : डॉ . भारत भूषण ने आज कठुआ शहर में करीब 15 लाख रुपये की लागत से तैयार दो विकास कार्यों का उद्घाटन कर उन्हें आम जनता को समर्पित किया।

उद्घाटन किए गए कार्यों में अपर शिवा नगर में देश बंधु किरयाना स्टोर से अशोक कुमार के घर तक सड़क की ब्लैकटॉपिंग तथा वार्ड नंबर–21 में मोहनिंदर पाल एसआरटीसी के घर से आगे तक सड़क की ब्लैकटॉपिंग शामिल है।

विधायक ने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी तथा लोगों को बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति देना समय की आवश्यकता है और आने वाले समय में भी विभिन्न वार्डों में नए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर सिटी मंडल अध्यक्ष राहुल देव शर्मा, ललित कांगला, सीमा कपूर, अशोक शर्मा, विजय शर्मा, अमित सूदन, अनिरुद्ध शर्मा, पूर्व पार्षद भानु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

रू 3 करोड़ की रामकोटदूबूल सड़क का विधायक सतीश शर्मा ने किया शिलान्यास, कई विकास कार्यों का भी उद्घाटन

सबका जम्मू कश्मीर

बिलावर/कठुआ। विधायक बिलावर सतीश शर्मा ने शनिवार को नाबार्ड योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 1.75 किलोमीटर लंबी रामकोटदूबूल सर्कुलर रोड का शिलान्यास किया। इस सड़क के बनने से बूल और कोरिथियाल गांवों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर विधायक ने एमएलए सीडीएफ 2025–26 के तहत रामकोट, नगरोटा गुज्जरू, धर्मकोट, ददवाड़ा, फिंटर, देवाल, किशनपुर और सुकराला क्षेत्रों में पूरे हुए कई विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया।

इनमें देवाल के सूका तालाब में सामुदायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी), राजपूत सभा हॉल के पास चौनल फेंसिंग, ग्राउंड लेवलिंग और पानी की बड़ी टंकी का निर्माण तथा सुकराला में गुरु आश्रम के निकट साम. ुदायिक भवन का निर्माण शामिल है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सतीश शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का समान और तेज विकास करना है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी।

इस मौके पर बीडीओ बिलावर शैलेंद्र कुमार ने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं ताकि जनता को लंबे समय तक लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रति. निधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने विकास कार्यों की सराहना करते हुए विधायक का धन्यवाद किया।

नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 2026 के तहत उस्मान मेमोरियल में झंगर बटालियन ने जागरूकता प्रोग्राम किया

सबका जम्मू कश्मीर

नौशहरा/जम्मू। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 2026 के हिस्से के तौर पर, झंगर बटालियन ने उस्मान मेमोरियल में युवा वॉलंटियर्स, स्पोर्ट्स कोच और आस–पास के गांवों के सीनियर सिटिजन और स्कूल टीचरों के लिए एक जागरूकता और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया। इस पहल का मकसद हिस्सा लेने वालों को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के नुकसानदायक असर और युवाओं में एक हेल्दी, डिसिप्लिन्ड और ड्रग–फ्री लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने की अहमियत के बारे में बताना था।प्रोग्राम के दौरान, हिस्सा लेने वालों को नशे के गलत इस्तेमाल के शुरुआती चेतावनी संकेतों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके बुरे असर और नशे से जुड़े सामाजिक नतीजों के बारे में बताया गया।

कमजोर युवाओं की पहचान करने और उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की ओर गाइड करने में माता–पिता, टीचरों, सीनियर सिटिजन और कम्युनिटी लीडर की अहम भूमिका पर खास जोर दिया गया।सेशन में युवाओं में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने में पीयर काउंसलिंग, लीडरशिप और कम्युनिटी सपोर्ट की अहमियत पर भी ज़ोर दिया गया।

नशे की लत से बचने के असरदार तरीकों के तौर पर स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पर चर्चा की गई, और पार्टिसिपेंट्स को युवा पीढ़ी को हेल्दी और प्रोडक्टिव कामों के लिए मोटिवेट करने के लिए बढ़ावा दिया गया। स्कूल टीचर्स के साथ एक खास बातचीत में स्टूडेंट्स के शुरुआती बिहेवियरल इंडिकेटर्स, काउंसलिंग के तरीकों और एक सपोर्टिव एजुकेशनल माहौल बनाने की अहमियत पर फोकस किया गया। सीनियर सिटिज़न्स को भी कम्युनिटी अवेयरनेस की कोशिशों में एक्टिवली हिस्सा लेने और गाइडेंस और सोशल सपोर्ट के ज़रिए युवाओं को मेंटर करने के लिए बढ़ावा दिया गया।प्रोग्राम एक इंटरैक्टिव चर्चा के साथ खत्म हुआ, जहाँ पार्टिसिपेंट्स ने अपने विचार शेयर किए और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 2026 की भावना के तहत एक ड्रग–फ्री और हेल्दी समाज बनाने के अपने कमिटमेंट को दोहराया।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

राँजड़ी, जम्मू में सद्गुरू श्री मधुपरमहंस जी महाराज का संदेशः माता-पिता की सेवा करें, शरीर के घमंड से बचें और नाम-सुमिरन अपनाएं

सबका जम्मू कश्मीर

राँजड़ी (जम्मू) : साहिब बंदगी के सद्गुरु श्री मधुपरम. हंस जी महाराज ने आज राँजड़ी, जम्मू में आयोजित सत्संग में अपने प्रवचनों की अमृतवर्षा करते हुए संगत को जीवन जीने की सही राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि जीवन कैसे जीना है।

सद्गुरु ने कहा कि आज के समय में कई बच्चे अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते और उनके वृद्ध होने पर उनका अनादर करते हैं, जो एक बड़ा पाप है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता जीवनभर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, इसलिए संतान सदैव उनके ऋणी रहती है। माता-पिता चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनकी सेवा और सम्मान करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता कभी डांटें या कठोर शब्द कहें तो भी उनका जवाब नहीं देना चाहिए। उनकी सेवा से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-शांति आती है।

प्रवचन के दौरान सद्गुरु ने शरीर के घमंड से बचने की सीख देते हुए कहा कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है।

इसकी सुंदरता और शक्ति स्थायी नहीं है, इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुरु और नाम की महिमा सबसे बड़ी है। नाम-सुमिरन करने से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और एक अदृश्य शक्ति हर समय उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करती है। उन्होंने संगत से नियमित रूप से सुमिरन करने और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सद्गुरु के प्रेरणादायक विचारों को श्रद्धापूर्वक सुना।

जनसंपर्क अभियान को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भारतीय जनता पार्टी अनुस. ूचित जाति मोर्चा जम्मू-कश्मीर की एक संगठनात्मक बैठक मंगलवार को त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी जनसंपर्क अभियान, जनकल्याण कार्यक्रमों तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

बैठक को भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने मुख्य रूप से संबो. धित किया।

इस अवसर पर पार्टी के उपाध्यक्ष एवं मोर्चा प्रभारी भारत भूषण, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष धर्मिंदर कुमार, सह प्रभारी जगदीश भगत, महासचिव मोहिंदर भगत और राहुल हंस भी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में अशोक कौल ने मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सभी 162 मंडलों में टीमों का गठन किया जाए और संगठनात्मक ढांचे को प्रत्येक बूथ तक विस्तारित किया जाए ताकि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।

इन उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं, विकास कार्यों और परिवर्तनकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।

अशोक कौल ने कहा कि अनुस. ूचित जाति मोर्चा सामाजिक समरसता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने मोर्चा नेताओं से गुरुजनों और संतों की जयंती तथा निर्वाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया, जिनमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने में सहायक होंगे।

उन्होंने आने वाले दिनों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को भी व्यापक स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए।

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537

दूरसंचार विभाग

डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896

जम्मू नगर पालिका

जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440

डाक सेवाएँ

मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863

अग्निशमन सेवाएँ

नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026

रसोई गैस डीलर

चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455

पावर हाउस

गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776

परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813

अस्पताल

जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डैंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739

नर्सिंग होम

मददन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

एलजी सक्सेना ने लद्दाख में नशामुक्ति केंद्रों के कामकाज की समीक्षा की

सबका जम्मू कश्मीर

लेह : लद्दाख में मादक पदार्थों के सेवन के मामलों में चिंताजनक वृद्धि और इससे जुड़ी बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के साथ एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लद्दाख में मादक पदार्थों के सेवन की स्थिति और वहां के नशामुक्ति केंद्रों (डीडीसी) के कामकाज की समीक्षा की गई। हाल के महीनों में लद्दाख में मादक पदार्थों के सेवन के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, विशेष रूप से युवाओं, नाबालिगों और यहां तक घ्कि लड़कियों में। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त पाए गए हैं।

बैठक के दौरान, उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि अप्रैल 2025 से, लेह स्थित एसएनएम अस्पताल के मनोचिकित्सा ओपीडी में अफीम से संबंधित 101 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 237 मामलों की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, भांग से संबंधित 25 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 39 मामलों की निगरानी की जा रही है। साथ ही, यह भी बताया गया कि 64 मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित मरीजों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है।

विचार–विमर्श के दौरान, लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) के युवा विंग के अध्यक्ष ने शराब की दुकानों में शराब की अनुपलब्धता की ओर ध्यान दिलाया, जिसके कारण कई लोग मादक द्रव्यों के सेवन की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार किया जाए और मौजूदा शराब की दुकानों में शराब उपलब्ध कराई जाए। मनोचिकित्सकों ने उन मामलों पर भी प्रकाश डाला, जहां रोजाना शराब पीने के आदी लोग लद्दाख में शराब की

अनुपलब्धता में अक्सर हिंसक और प्रलाप जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और दवाओं से उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल ने लद्दाख में मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए, एलजी सक्सेना ने कई निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैंरू

मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करना और उसे नष्ट करना। लद्दाख पुलिस मादक पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं और तस्करों के खिलाफ शून्य–सहिष्णुता नीति अपनाएगी।

क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जोजी–ला और सरचू सहित लद्दाख के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की अचानक जांच की जाएगी।

स्थानीय टैक्सियों की अचानक तलाशी ली जाएगी। यदि टैक्सी चालक मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके वाहन जब्त किए जाएंगे।

स्कूलों, कॉलेजों और पर्यटन स्थलों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

पुनर्वास और उपचार सहायता चाहने वाले माता–पिता और रोगियों के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन के रूप में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर ७112९ का संचालन करना।

प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 112 का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली कॉलों का जवाब देने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स और परिचारक वाली समर्पित टीमों का गठन करना।

संबंधित नशामुक्ति केंद्र उपचार और पुनर्वास के लिए मरीजों के परिवहन हेतु एक विशेष वाहन की व्यवस्था करेंगे।

नशामुक्ति केंद्रों का नाम बदलकर अधिक उपयुक्त और सामाजिक रूप से संवेदनशील रखा जाएगा। नशामुक्ति

केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों में महिला मरीजों और किशोरों के लिए अलग सुविधाएं और कमरे बनाए जाएंगे।

मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित व्यापक और समेकित आंकड़ों को अस्पतालों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्लीनिकों से एकत्रित करके रोगियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना, ताकि मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए एक प्रभावी दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा सके।

देश व समाज हित में डीजल व पेट्रोल की बचत के साथ–साथ स्थाई सादगी समय की मांग!

वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे-धीरे रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया।

दीपक कुमार त्यागी

अमेरिका–ईरान युद्ध के चलते जिस समय पूरे विश्व के सामने ऊर्जा संकट व मंहगाई सुरसा राक्षसी की तरह मूंह खोलकर के देश की दौलत को निगलने के लिए खड़ी है, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीजल व पेट्रोल को बचाने व सोना ना खरीदने की सभी देशवा. सियों से अपील की है, क्योंकि मोदी की इस अपील पर अमल करने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला बोझ कम से कम कुछ तो कम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी के द्वारा चलाई जा रही इस राष्ट्रहित की मुहिम में शामिल होने की होड़ लग गई है। हालांकि अभी तो अधिकतर लोग सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस मुहिम में ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन सांकेतिक ही सही एक बहुत अच्छी पहल में कम से कम लोगों के जुड़ने की शुरुआत तो हुई और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस पहल पर बड़े पैमाने पर आम लोग भी अमल करेंगे।

वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे–धीरे रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया। जिसके बाद से ही देश भर में ज्यूडिशियरी, शीर्ष नौकरशाह, कर्मचारी व आम जनमानस तक भी मोदी की इस मुहिम में अब बड़े पैमाने पर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शासन–प्रशासन के शीर्ष स्तर पर काबिज बैठे हुए ताकतवर लोगों में देश भर में वाहनों के लंबे–चौड़े काफिले का त्याग करने की फिलहाल तो एक होड़ लगी हुई है। हालांकि उन लोगों का यह कदम वास्तव में दिल से खर्चों में कटौती करते हुए जीवन में सादगी अपनाने की धरातल पर एक स्थाई पहल है या सिर्फ मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी कुछ पोस्ट डालकर के वाहवाही लूटने की एक नौटंकी मात्र है, यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम युद्ध के माहौल के चलते जब पूरी दुनिया ऊर्जा व आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील पर भारत में धरातल पर अमल शुरू होना देश व समाज हित के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।

लेकिन विचारणीय तथ्य यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह मुहिम कुछ समय की ना होकर के देश व समाज हित में धरातल पर दीर्घकालीन स्थाई रूप ले पायेगी, हालांकि यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्धों के चलते बेहद ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, उस माहौल का स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब वह दौर आ गया है जब देश व समाज के हित में जनता के टैक्स के पैसे के दम पर राजा–महाराजाओं की तरह पूरी शानो–शौकत व ठाट–बाट से जीवन व्यतीत कर रहे शासन–प्रशासन के लोग सादगी से जीवनयापन करने की आम जनमानस के सामने नज़ीर पेश करते हुए लोगों को भी ष्सादा जीवन उच्च विचारष् के लिए प्रेरित करें। वैसे भी देखा जाए तो अब देश व दुनिया में वह दौर शुरू हो गया है, जब देश व समाज के हित की बातें सिर्फ और सिर्फ सरक. ारी दफ्तरों में बैठकर के आम जनमानस पर अपने विचार या नियम–कानून बना कर के थोप देने मात्र से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उस पर अमल करवाने के लिए शासन–प्रशासन में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी स्वयं अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सादगी व जवाबदेही को अपनाकर उदाहरण पेश करना चाहिए, तब ही आम जनमानस भी उन लोगों की देखा–देखी उस पर अमल करने का कार्य करेगा।

लेकिन आज के वीवीआईपी बनकर के दिखाने वाले दौर में जिस तरह के राजसी ठाट–बाट के साथ कुछ राजनेताओं व शासन–प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग सरकारी व निजी दौरों के दौरान अनाप–शनाप खर्चा करते हैं, क्या ऐसे लोग के द्वारा देश व समाज हित में उन सभी अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही कटौती करने की पहल करके जनता के सामने एक बड़ी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए।

विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरक. ारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी मंहगी गाड़ियों के लंबे–चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपना भौकाल बनाने के लिए व दिखावे के लिए ली गयी अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को भी अब बिल्कुल सीमित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चंद लोग सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों की कृपा से सरकारी अमले की आड़ में जनता के टैक्स के पैसों पर मौज मस्ती करते हुए जनता का ही आये दिन उत्पीड़न करते हैं, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सांठ–गांठ करके हमारे प्यारे देश में धनपशु, दलाल व अपराधी तक भी सरकारी सुरक्षा व सुविधाओं के भौकाल का आनंद लें रहे हैं, जो नियम कायदे व कानून पसंद देशभक्त देशवासियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। देश व समाज हित में जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दी गई धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उधोग–धंधों आदि के साथ–साथ देश के सर्वांगीण विकास पर खर्च हो। देश की जनता के टैक्स का धन देश के विकास और आम जनमानस की भलाई में लगे, न कि वीवीआईपी बनने की चाहत के बेफिजूल के खर्चो और शानो–शौकत में लगे। इसलिए अब देश व समाज हित में वह समय आ गया है जब शासन व प्रशासन में बैठे लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना ना खरीदने व डीजल और पेट्रोल बचाने की पहल को दो कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं ही अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सरलता व सादगी अपनाकर देश व समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेंगें और भारत का नव निर्माण करते हुए देश को विश्व गुरु बनायेंगे।

– दीपक कुमार त्यागी
अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नगरी ऐरवा मोड़ फिर बना झगड़ों का गढ़, लगातार हो रही घटनाओं से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत

सबका जम्मू कश्मीर

नगरी/कठुआ। नगरी क्षेत्र के मुख्य ऐरवा मोड़ पर पिछले दो सप्ताह से लगातार झगड़ों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय दुक. ानदारों और आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। बीते सप्ताह यहां एक बार फिर युवाओं के दो गुटों के बीच तीखा विवाद और मारपीट हुई, जिसने क्षेत्र में कानून–व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, हालिया झगड़ा एक सप्ताह पहले हुए विवाद का ही परिणाम बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि क्षेत्र में रहने वाले नागरिक और व्यापारी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

दुकानदारों का कहना है कि ऐरवा मोड़ अब झगड़ों का केंद्र बनता जा रहा है। उनका आरा. ोप है कि पुलिस को समय रहते सख्त कदम उठाकर ऐसे तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए थी, ताकि स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके। स्थानीय निवासियों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी और गंभीर घटना घट सकती है।

गौरतलब है कि इस मुद्दे को पहले भी स्थानीय मीडिया में प्रमुखता से उठाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद झगड़ों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी क्षेत्र में शांति और कानून–व्यवस्था बनाए रखना है तथा लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों ने एसएसपी कठुआ तथा नगरी चौकी प्रभारी से मांग की है कि ऐरवा मोड़ पर नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और चौबीस घंटे निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद नगरी पुलिस कितनी सतर्कता और सक्रियता दिखाती है तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती है।

कठुआ पुलिस की बड़ी सफलता : 2 चोरी के मामले सुलझाए, 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, जम्मू–कश्मीर पुलिस ने चोरी और वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो मामलों का सफलतापूर्वक खुला. सा किया है। पुलिस ने दो आरो. पियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, पहला मामला शिवा नगर कठुआ का है, जहां एक घर में चोरी कर दो लैपटॉप, एक रेडमी 5जी मोबाइल फोन और अन्य सामान चुरा लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी नितीश शर्मा उर्फ टोका को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए दोनों लैपटॉप और मोबा. इल फोन बरामद कर लिया।

दूसरा मामला मोटरसाइकिल चोरी का था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चार अन्य संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद कर जब्त कर ली गईं।

पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में की गई।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गति. विधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके।

सीएमआरएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के घर और अन्य लोगों के घरों पर छापा मारा

सबका जम्मू कश्मीर

तिरुवनंतपुरम : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के आवासों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई उनकी बेटी से जुड़े सीएमआरएल मामले में धन शोधन के सिलसिले में की गई है। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई इस छापेमारी में राजधानी, एर्नाकुलम, कन्नूर और बेंगलुरु (कर्नाटक) में कुल 10 परिसरों को शामिल किया गया। इस छापेमारी में सीएपीएफ कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा भी शामिल थी। तलाशे गए परिसरों में 81 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री का बेकरी जंक्शन क्षेत्र में स्थित किराए का मकान, उनके दामाद और पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास का कोझिकोड स्थित आवास, कन्नूर में विजयन परिवार का एक घर और को. चीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े अन्य स्थान शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि विजयन के घर की तलाशी इसलिए ली गई है क्योंकि जांच में उनकी बेटी वीना विजयन भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तलाशी के दौरान अपने घर पर ही थे। अधिक. ारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान निवेश और सावधि जमा से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए।

एक युग का अंत : अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह का निधन

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : अनुभवी खेल प्रशासक और एशियाई खेलों में भारत के पहले शूटिंग स्वर्ण पदक विजेता रणधीर सिंह का बुधवार को वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनके निधन से देश के खेल जगत में एक युग का अंत हो गया, जिस पर उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अमिट छाप छोड़ी।

सिंह 79 वर्ष के थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनकी पत्नी विनीता और तीन बेटियां महिमा, सुनैना और राजेश्वरी हैं, जो स्वयं भी एक निशानेबाज हैं।

हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे खेल प्रशासक के रूप में उनका चार दशकों से अधिक का सफर समाप्त हो गया।

उन्हें 2024 में चार साल के कार्यकाल के लिए ओसीए के शीर्ष पद पर चुना गया था, इससे पहले वे 1991 से 2015 तक महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। भारतीय

राष्ट्रीय राइफल्स एसोसिएशन (एनआरएआई) के सचिव राजीव भाटिया ने कहा, ाहरे दुख के साथ, हम राजा रणधीर सिंह के निधन की दुखद खबर साझा करते हैं, जिनका आज 27 मई 2026 को निधन हो गया।

एक प्रतिष्ठित ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत, एशिया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सबसे सम्मानित खेल प्रशासकों में से एक, राजा रणधीर सिंह ने शूटिंग खेलों और ओलंपिक आंदोलन के विकास में अमूल्य योगदान दिया।ा "भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ और संपूर्ण शूटिंग जगत इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार एवं प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें," उन्होंने आगे कहा।

सिंह के निधन पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई, जिसमें वर्तमान और पूर्व प्रशासकों के साथ–साथ शीर्ष खिलाड़ियों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय खेलों में उनकी भूमिका की सराहना की।

सिंह के शानदार खेल करियर में पांच ओलंपिक में भागीदारी और 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक शामिल है, जिसके लिए उन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने टोक्यो 1964 (रिजर्व शूटर), मैक्सिको 1968, म्यूनिख 1972, मॉन्ट्रियल 1976, मॉस्को 1980 और लॉस एंजिल्स 1984 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आईडीपीएस जम्मू में प्रथम ऑन्कोअसेंबली आयोजित

तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने का लिया संकल्प, विद्यार्थियों ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में दिखाया उत्साह

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर आईडीपीएस जम्मू में प्रथम ऑन्कोअसेंबली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया और एलबीएनआरओएच के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में डॉ. दीपक अबरोल, शशि खजूरिया, मालविका खजूरिया, डॉ. सुरभि कुद्यार, यासिर चौहान और मजार इकबाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "तंबाकू पर प्रति. बंध दृ समय की आवश्यकता" विषय पर आयोजित वाद–विवाद प्रतियोगिता रही। विद्यार्थियों ने तंबाकू के दुष्प्रभावों और इसके सामाजिक प्रभावों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता में दयाना शाह ने प्रथम, अंजन कौर ने द्वितीय तथा हरनिध कौर कंधारी ने

तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जैसमीत कौर और मतीबा मुगल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ. दीपक अबरोल ने सभी को तंबाकू मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूक बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी ऑन्कोलॉजी पार्लियामेंट और क्राबेकॉन कैंसर कन्वेंशन 2026 की गतिविधियों की शुरुआत है, जिनका उद्देश्य कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने तंबाकू से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। आयोज. कों ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से तंबाकू मुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।

बिज्जत गांव में विधायक ने लगाया जनता दरबार, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव बिज्जत में विधायक ने जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी तथा अन्य विकास कार्यों से जुड़ी कई मांगें और समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं।

विधायक ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी इलाका विकास से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि गर्मियों के मौसम में जल संकट को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीणों ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वह लगातार दूरदराज क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

इस मौके पर पीएचई विभाग, पीएमजीएसवाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जेकेपीडीसी विभाग तथा बीडीओ विभाग के जेई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में लखनपुर मंडल अध्यक्ष सुमन वाला, पूर्व सरपंच दिलावर सिंह, पूर्व सरपंच उत्तम सिंह, कैप्टन पवन शर्मा, राज सिंह, थरू राम (मखनु), कुलदीप शर्मा, धर्म सिंह सहित गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

राजबाग–हरियाचक रोड की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा, किया जोरदार प्रदर्शन

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन, राजबाग से लेकर हरियाचक तक सड़क की खस्ता हालत को लेकर शनिवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि सड़क तालाब जैसी नजर आने लगी। सड़क पर पड़े बड़े–बड़े गड्ढों के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जुग्याल, पभडमा और आसपास के गांवों के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 7–8 वर्षों से सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है और जगह–जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे वाहन चलाना और पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरा.ेप लगाया कि क्षेत्र में दो–दो विधायक होने के बावजूद सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जनता की समस्याओं की कोई सुध नहीं लेते।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जसरोटा और हीरानगर विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को इस सड़क की दुर्दशा की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रति.निधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

भीषण गर्मी में सेहत से खिलवाड़ न करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें – डॉ. सामिया मोहन

"स्वस्थ खाएं, स्वस्थ पियें और गर्मी में सावधानी अपनायें"– डॉ. सामिया मोहन || तेज धूप, संक्रमण और मच्छर जनित बीमारियों का बढ़ा खतरा; विशेषज्ञों ने दी सावधानी बरतने की अहम सलाह

सबका जम्मू कश्मीर

गर्मी का मौसम अपने साथ केवल तपती धूप ही नहीं, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ भी लेकर आता है। बढ़ते तापमान, धूलभरी हवाआ.ं और उमस के कारण लोगों में हीट स्ट्रोक, थकान, त्वचा रोग, पेट संबंधी संक्रमण और वायरल बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। विभागीय सर्जन एएसकॉम्स (ोब्डै) की डॉ. सामिया मोहन ने बताया कि गर्मियों में विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और पहले से बीमार लोग अधिक जोखिम में रहते हैं। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। डॉ. मोहन के अनुसार शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ–साथ इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और दही का सेवन लाभकारी है। उन्होंने हल्के, ढीले और पूरे शरीर को ढकने

वाले कपड़े पहनने की सलाह दी, ताकि गर्मी और त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव हो सके।

उन्होंने चेतावनी दी कि गर्मियों में स्वच्छता की अनदेखी कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। दूषित भोजन और अस्वच्छ पेयजल के कारण टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलती हैं। इसलिए केवल ताजा, स्वच्छ और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।

मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी उन्होंने लोगों को सतर्क किया। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें तथा मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट का नियमित इस्तेमाल करें। डॉ. मोहन ने यह भी कहा कि आँखों के संक्रमण और ऑपरेशन के बाद घाव में संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और किसी भी समस्या के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें।

गर्मी में स्वस्थ रहने के आसान उपाय
दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ
हल्के और ढीले कपड़े पहनें
दोपहर की तेज धूप से बचें
हाथ और भोजन की स्वच्छता बनाए रखें
ठंडी और हवादार जगह पर रहें
हल्का, ताजा और पौष्टिक भोजन करें
शरीर में पानी की कमी के संकेतों को नजर. अंदाज न करें

स्वस्थ जीवन का सरल मंत्र
"स्वस्थ खाएं, स्वस्थ पियें और गर्मी में सावधानी अपनायें।"

अवैध प्रवासन के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं : गृह मंत्रालय

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अवैध प्रवासन के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका प्रभाव शहरी केंद्रा.ं, औद्योगिक गलियारों, आदिवासी क्षेत्रों और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों तक भी फैल गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के सेवा.निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर की अध्यक्षता में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीडीसी) के गठन के संबंध में कहा गया है कि अवैध आप्रवासन के कारण हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से व्यापक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ष्अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणोंष से भारत भर में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी।

नई दिल्ली में मुख्यालय वाली इस समिति में जनगणना आयुक्त, सेवा.निवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि भी सदस्य होंगे और यह एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शाह ने मंगलवार को कहा था, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी–1) इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि देश के कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखे गए हैं, जो ष्सामान्य प्रजनन या मृत्यु दर के रुझानों के कारण नहीं हैं बल्कि अवैध अप्रवासन, अनियमित जनसंख्या गतिशीलता और प्रशासनिक शिथिलता जैसे बाहरी असामान्य कारकों के कारण उभर रहे हैं।

जम्मू–कश्मीर में ईद–उल–अज़हा का त्योहार वैश्विक शांति के लिए प्रार्थनाओं के साथ मनाया गया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर में बुधवार को ईद–उल–अज़हा धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाई गई। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों ने सुबह विशेष नमाज अदा कर अमन, खुशहाली और इंसानी भाईचारे की दुआ मांगी। ईद के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रशासन की ओर

से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

ईद–उल–अज़हा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पैगंबर इब्राहिम ने ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हुए अपने पुत्र की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी। उनकी इसी निष्ठा और बलिदान की भावना को याद करते हुए मुसलमान इस दिन पशुओं की कुर्बानी देते हैं और जरूरतमंदों के बीच मांस वितरित करते हैं।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पर मंथन, शहरी विकास और बाढ़ प्रबंधन पर जोर

हितधारकों की बैठक में बाजार में जाम, पार्किंग, ड्रेनेज और कठुआ खड्ड के चौनलाइजेशन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए तैयार किए जा रहे जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को लेकर गुरुवार को डीसी कार्यालय परिसर कठुआ में हितधारकों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के सुनियोजित विकास, बाढ़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण, विधायक जसरोता राजीव जसरोतिया, उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महिमा मदान, मुख्य योजना अधिकारी रणजीत ठाकुर, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के सेंटर ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रतिनिधि सहायक प्रोफेसर डॉ. साक्षी ने वर्चुअल माध्यम से परियोजना की प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति में मास्टर प्लान की रूपरेखा बताते हुए योजनाबद्ध शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं और आर्थिक गति. विधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कठुआ शहर और आसपास के पात्र क्षेत्रों को अंतिम मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण भी जल्द शुरू किया जाएगा।

विधायक डॉ. भारत भूषण ने बैठक में कठुआ खड्ड के चौनलाइजेशन, शहर में अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, मुख्य बाजार में बढ़ती भीड़भाड़, रेहड़ी–फड़ी वालों के पुनर्वास और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं जमीनी जरूरतों के अनुरूप और तथ्य आधारित होनी चाहिए।

वहीं विधायक राजीव जसरोतिया ने शहर से सटे क्षेत्रों के संतुलित और व्यवस्थित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपायुक्त राजेश शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार हो और आम लोगों के हित भी सुरक्षित रहें।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों से लगातार सुझाव लिए जाएंगे तथा सर्वेक्षण पूरा होने के बाद अगली बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गुजरात तट से 1,150 करोड़ रूपये की कोकीन जब्त; 3 विदेशी गिरफ्तार

सबका जम्मू कश्मीर

अहमदाबाद : गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुंद्रा बंदरगाह के पास एक जहाज से लगभग 1,150 करोड़ रुपये मूल्य की 115 किलोग्राम को. कीन जब्त की और तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गुजरात के पुलिस महानिदेशक केएलएन राव ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मालवाहक जहाज श्यूरोपश के कच्छ जिले के मुंद्रा बंदरगाह के पास लंगर डालने से पहले यह खेप लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कराची (पाकिस्तान) से होकर गुजरी थी।

एक आरोपी के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में ब्राजील में जहाज पर प्रतिबंधित सामान लादा गया और चालक दल के अन्य सदस्यों की जानकारी के बिना उसे गुप्त रूप से मोटर रूम में छिपा दिया गया था। आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जुमा नासिर उमर नाम के एक तंजानियाई नागरिक को नाव से गिरफ्तार किया गया, जबकि गुजरात एटीएस ने दिल्ली पुलिस की मदद से राजधानी के द्वारका इलाके से दो अन्य विदेशी नागरिकों को पकड़ा, जिन्हें सामान लेना था।

डीजीपी ने बताया कि एक अन्य संदिग्ध, जो तंजानियाई नागरिक है और ऑपरेशन के दौरान समुद्र में कूद गया था, उसकी तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि

खेप के थैलों से जीपीएस उपकरण, उपग्रह संचार उपकरण और एयरटैग भी जब्त किए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि परिवहन के दौरान प्रतिबंधित सामान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया गया होगा।

राव ने बताया कि आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) और तटरक्षक बल ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। एटीएस के एक अधिकारी को खुफिया जानक. ारी मिली थी कि ब्राजील से समुद्री मार्ग से कोकीन की एक बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है।

इस जानकारी के आधार पर एटीएस अधिकारी 25 मई की रात को मुंद्रा पहुंचे और तटरक्षक बल के साथ समन्वय स्थापित करके संयुक्त अभियान

शुरू किया। राव ने कहा, ७26 मई की सुबह संयुक्त दल ने बाहरी बंदरगाह पर श्यूरोपश नामक जहाज को रोका और तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान, टीम को पता चला कि जहाज पर नशीले पदार्थों से भरे छह बैग छिपाए गए थे।

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार